



भारत का राजपत्र The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 26] नई दिल्ली, जुलाई 1—जुलाई 7, 2018, शनिवार/आषाढ़ 10—आषाढ़ 16, 1940
No. 26] NEW DELHI, JULY 1—JULY 7, 2018, SATURDAY/ASADHA 10—ASADHA 16, 1940

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं
Statutory Orders and Notifications Issued by the Ministries of the Government of India
(Other than the Ministry of Defence)

वित्त मंत्रालय
(वित्तीय सेवाएं विभाग)

नई दिल्ली, 2 जुलाई, 2018

का.आ. 1025.—बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 (1970 का 5) की धारा 3 की उप-धारा (2क) के दूसरे परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से, एतद्वारा, बैंक आफ महाराष्ट्र की प्राधिकृत पूंजी को तीन हजार करोड़ रुपए से बढ़ाकर चार हजार करोड़ रुपए करती है।

[फा.सं. 11/4/2009—बीओए]

ए. के. घोष, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Financial Services)
New Delhi, the 2nd July, 2018

S.O. 1025.—In exercise of the powers conferred by the second proviso to sub-section (2A) of section 3 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (5 of 1970), the Central Government, after consultation with the Reserve Bank of India, hereby increases the authorised capital of Bank of the Maharashtra from three thousand crore rupees to four thousand crore rupees.

[F.No.11/4/2009-BOA]
A. K. GHOSH, Under Secy.

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली, 13 अप्रैल, 2018

का.आ. 1026.—केन्द्रीय सरकार सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) अधिनियम, 1971 (1971 का 40) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से कमांडेंट को संपदा अधिकारी के रूप में नियुक्त करती है और उक्त प्रयोजन के लिए का. आ. 1421 तारीख 28 मई 2011 द्वारा भारत के राजपत्र भाग-II धारा 3 उप-धारा (ii) में प्रकाशित गृह मंत्रालय की अधिसूचना में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना में, क्रम सं. 4 की सारणी में और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा अर्थात्:-

क्र.सं.	अधिकारी	स्थानीय सीमाएं या सरकारी स्थान
(1)	(2)	(3)
"4.(क)	कार्यालय के प्रमुख का प्रभार संभालने वाले पुलिस उप महानिरीक्षक	केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के सभी रेंज मुख्यालयों (प्रशासनिक या परिचालनिक) या सभी समूह केन्द्रों के परिसर।
(ख)	केन्द्रीय प्रशिक्षण महाविद्यालय, प्रतिविद्रोहिता एवं आतंकवाद विरोधी स्कूल, और कमाण्डो बटालियन फॉर रिजाल्यूट एक्शन स्कूल ऑफ जंगल वारफेयर एण्ड टेक्टिक्स, के सभी कमांडेंट।	केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के केन्द्रीय प्रशिक्षण महाविद्यालय, प्रतिविद्रोहिता एवं आतंकवाद विरोधी स्कूल और कमाण्डो बटालियन फॉर रिजाल्यूट एक्शन स्कूल ऑफ जंगल वारफेयर एण्ड टेक्टिक्स।

[फा.सं. ए. II-1/2017-प्रशा.1-डीए-IV/सीआरपीएफ/एमएचए-पीएफ-III]

जोगिन्द्र प्रसाद, अवर सचिव

नोट : प्रमुख अधिसूचना भारत के राजपत्र भाग-II, खण्ड-3, उप-खण्ड-(ii), एस.ओ.-1421 तारीख 28 मई, 2011 में प्रकाशित की गई थी।

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

New Delhi, the 13th April, 2018

S.O. 1026.—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Public Premises (Eviction of Unauthorized Occupants) Act, 1971 (40 of 1971), the Central Government hereby appoints Commandant as Estate Officer, with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette and for that purpose makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Home Affairs, published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section(ii), vide S.O 1421, dated the 28th May, 2011, namely :-

In the said notification, in the table, for serial number 4 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely :-

Sl. No.	Officers	Local limits of public premises
(1)	(2)	(3)
"4. (a)	Deputy Inspector General of Police holding the charges of Head of Office.	Premises of the Central Reserve Police Force, at all Range Headquarters (Administrative or Operational) or all Group Centers.
(b)	All Commandants of Central Training Colleges; Counter Insurgency and Anti-Terrorism School; and Commando Battalion for Resolute Action School of Jungle Warfare and Tactics.	Premises of the Central Reserve Police Forces, at respective Central Training Colleges; Counter Insurgency and Anti-Terrorism Schools; and Commando Battalion for Resolute Action School of Jungle Warfare and Tactics."

[F. No. A. II-1/2017-Adm.I-DA-IV/CRPF/MHA-PF-III]

JOGINDER PRASAD, Under Secy.

Note : The principal notification was published in the Gazette of India, Part-II, Section-3, Sub-Section-(ii), vide S.O.1421, dated the 28th May, 2011.

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय**(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)**

नई दिल्ली, 29 जून, 2018

का.आ. 1027.—केंद्रीय सरकार, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 24 की उपधारा (8) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, रांची, झारखंड राज्य में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा सौंपे गए, दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन (केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो) द्वारा संस्थित मामलों का परीक्षण न्यायालयों तथा विधि द्वारा स्थापित पुनरीक्षण या अपीलीय न्यायालयों में अपीलों/पुनरीक्षणों या उनसे उद्भूत अन्य मामलों के अभियोजन का संचालन करने के लिए, श्री सुशील रंजन दास अधिवक्ता को नियुक्ति की तारीख से तीन वर्षों या अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, के लिए विशेष लोक अभियोजक के रूप में नियुक्त करती है।

[फा. सं. 225/16/2016-एवीडी-2]

एस. पी. आर. त्रिपाठी, अवर सचिव

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS**(Department of Personnel and Training)**

New Delhi, the 29th June, 2018

S.O. 1027.—In exercise of the powers conferred by sub-section (8) of section 24 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974), the Central Government hereby appoints Shri Sushil Ranjan Das, Advocate as Special Public Prosecutor for conducting prosecution of cases instituted by Delhi Special Police Establishment (CBI) in the State of Jharkhand at Ranchi as entrusted to him by the Central Bureau of Investigation in the trial courts and appeals, revisions or other matters arising out of these cases in revisional or appellate courts established by law for a period of three years from the date of appointment or further orders, whichever is earlier.

[F.No. 225/16/2016-AVD-II]

S. P. R. TRIPATHI, Under Secy.

नई दिल्ली, 29 जून, 2018

का.आ. 1028.—केंद्रीय सरकार, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का अधिनियम सं0 2) की धारा 24 की उपधारा (8) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, श्री निखिल गोयल, अधिवक्ता को, दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन (केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो) द्वारा विशेष न्यायाधीश, तीस हजारी, दिल्ली के न्यायालय में संस्थित वाद सं0 आरसी.10(ए)/2017-एसी-3, नई दिल्ली का और उससे संबंधित और उसके आनुषंगिक किसी अन्य मामलों का संचालन करने के लिए, नियुक्ति की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए या मामले का निपटारा होने तक, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, विशेष लोक अभियोजक के रूप में नियुक्त करती है।

[फा. सं. 225/30/2017-एवीडी-2]

एस. पी. आर. त्रिपाठी, अवर सचिव

New Delhi, the 29th June, 2018

S.O. 1028.—In exercise of the powers conferred by sub-section (8) of section 24 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974), the Central Government hereby appoints Shri Nikhil Goel, Advocate as Special Public Prosecutor for conducting case No. RC 10(A)/2017-AC-III, New Delhi instituted by the Delhi Special Police Establishment (C.B.I) in the court of Special Judge, Tis Hazari, Delhi and any other matters connected therewith or incidental thereto for a period of three years from the date of appointment or disposal of the case whichever is earlier.

[F.No. 225/30/2017-AVD-II]

S. P. R. TRIPATHI, Under Secy.

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय**(स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग)**

नई दिल्ली, 23 अप्रैल, 2018

का.आ. 1029.—भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, 1956 (1956 का 102) की धारा 11 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् से परामर्श करके उक्त अधिनियम की प्रथम अनुसूची में, निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त प्रथम अनुसूची में, 'मान्यताप्राप्त आयुर्विज्ञान अर्हता' शीर्षक के अधीन [जिसे इसके आगे कालम (2) कहा गया है] "पश्चिम बंगाल स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, कोलकाता" के सामने अंतिम प्रविष्टि के पश्चात और 'पंजीकरण के लिए संक्षिप्तकरण' [जिसे इसके आगे कालम (3) कहा गया है] से संबंधित प्रविष्टि के संबंध में निम्नलिखित अंतस्थापित किया जाएगा, अर्थात्

(2)	(3)
"बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी"	एम.बी.बी.एस.
	(यह एक मान्यताप्राप्त आयुर्विज्ञान अर्हता होगी जब यह आईकेयर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसिस एंड रिसर्च, हल्दिया में केवल एम.बी.बी.एस. अकादमिक सत्र 2011-12 में प्रविष्ट छात्रों के संबंध में पश्चिम बंगाल स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, कोलकाता द्वारा प्रदत्त होगी।)

- नोट :**
1. दी गई ऐसी मान्यता अधिसूचना की तारीख से अधिकतम 5 वर्ष के लिए होगी और उसके बाद इसका नवीकरण करवाना होगा।
 2. मान्यता के 'नवीकरण' की प्रक्रिया वही होगी जो मान्यता प्रदान करने के लिए लागू होती है।
 3. अपेक्षित मान्यता का समय से नवीकरण करवाने में विफल रहने पर, परिणाम स्वरूप, निरपवाद रूप से संबंधित स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेश बंद हो जाएगा।

[सं. यू-12012/01/2018-एमई-1/एफटीएस. 3149999]

डी. वी. के. राव, अवर सचिव

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE**(Department of Health and Family Welfare)**

New Delhi, the 23rd April, 2018

S.O. 1029.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of the section 11 of the Indian Medical Council Act, 1956(102 of 1956), the Central Government, after consulting the Medical Council of India, hereby makes the following further amendments in the First Schedule to the said Act:

In the said First Schedule after "**The West Bengal University of Health Sciences, Kolkata**" and under the heading 'Recognized Medical Qualification' [Hereinafter referred to as column (2)], after the last entry and entry relating thereto under the heading 'Abbreviation for Registration' [Hereinafter referred to as column (3)], the following shall be inserted, namely:-

(2)	(3)
Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery	M.B.B.S.
	(This shall be a recognized medical qualification when granted by The West Bengal University of Health Sciences, Kolkata, in respect of students admitted in ICARE Institute of Medical Sciences & Research, Haldia in MBBS Course in the academic year 2011-12 only.)

- Note:** 1. The recognition so granted to an undergraduate courses for award of MBBS degree shall be for a maximum period of 5 years, upon which it shall have to be renewed.
2. The procedure for 'Renewal' of recognition shall be same as applicable for the award for recognition.
3. Failure to seek timely renewal of recognition as required shall invariably result in stoppage of admissions to the concerned undergraduate Course.

[No.U.12012/20/2018-ME.I/FTS.3149999]

D. V. K. RAO, Under Secy.

शुद्धि-पत्र

नई दिल्ली, 24 अप्रैल, 2018

का.आ. 1030.— इस विभाग की अधिसूचना सं. यू-12012/01/2017-एमई-1 (पार्ट 2) दिनांक 07.06.2017 के अनुक्रम में भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, 1956 (1956 का 102) की धारा 11 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् से परामर्श करके उक्त अधिनियम की प्रथम अनुसूची में, निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् —

उक्त अनुसूची में—

- क) “राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय” के समक्ष ‘पंजीकरण के लिए संक्षिप्तिकरण’ कालम (3) शीर्षक के अंतर्गत डॉक्टर ऑफ मेडिसिन (सोशल एंड प्रिवेंटिव मेडिसिन/कम्युनिटी मेडिसिन) मान्यताप्राप्त आयुर्विज्ञान अर्हता होगी जब यह शिमोगा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस में 2015 की बजाय 2014 को या बाद में प्रशिक्षित किए गए छात्रों को राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त होगी।”

[सं. यू-12012/01/2017-एमई-1 (पार्ट 2)]

डी. वी. के. राव, अवर सचिव

CORRIGENDUM

New Delhi, the 24th April, 2018

S.O. 1030.—In continuation to this Department's Notification No. U-12012/01/2017-ME-I (Pt-2) dated 07.06.2017 and in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of the section 11 of the Indian Medical Council Act, 1956(102 of 1956), the Central Government, after consulting the Medical Council of India, hereby makes the following further amendments in the First Schedule to the said Act, namely:-

In the said Schedule –

- a) against “Rajiv Gandhi University of Health Sciences” under the heading ‘Abbreviation for Registration’ (column 3), the Doctor of Medicine (Social & Preventive Medicine/Community Medicine) qualification shall be a recognized medical qualification when granted by Rajiv Gandhi University of Health Sciences in respect of students being trained at Shimoga Institute of Medical Sciences on or after 2014 instead of 2015”.

[No. U-12012/01/2017-ME-I (Pt. 2)]

D. V. K. RAO, Under Secy.

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय**(कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग)**

नई दिल्ली, 29 जून, 2018

का.आ. 1031.—केन्द्रीय सरकार, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग, राजभाषा (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग) नियमावली 1976 के नियम 10 के उपनियम (4) के अनुसरण में भा.कृ.अ.प.- केन्द्रीय आलू अनुसंधान केन्द्र, कुफरी को, जिसमें 80 प्रतिशत से अधिक कर्मचारियों ने हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है, एतद्वारा अधिसूचित करती है।

[फा. सं.13-10/2009-हिंदी/246-80]

राजेश कुमार, अवर सचिव

MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMER WELFARE**(Department of Agricultural Research and Education)**

New Delhi, the 29th June, 2018

S.O. 1031.—In pursuance of sub-Rule (4) of Rule 10 of the Official Language (use for official purpose of the Union) Rules 1976, the Central Government, Ministry of Agriculture & Farmer Welfare, Department of Agricultural Research & Education hereby notifies the ICAR-Central Potato Research Station, Kufri, Shimla, DPRS, Shimla where more than 80% of staff have acquired the working knowledge of Hindi.

[F.No. 13-10/2009-Hindi/246-80]

RAJESH KUMAR, Under Secy.

नागर विमानन मंत्रालय

नई दिल्ली, 26 जून, 2018

का.आ. 1032.—केन्द्रीय सरकार, राजभाषा (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग) नियम, 1976 के नियम 10 के उप-नियम (4) के अनुसरण में, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन विमानपत्तन निदेशक का कार्यालय, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, मैसूर हवाई अड्डा, मैसूर (कर्नाटक) जिसके 80 प्रतिशत से अधिक कर्मिकों ने हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है, को एतद्वारा अधिसूचित करती है।

[सं. ई-11014/9/2015-रा.भा.]

एस. के. मिश्रा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF CIVIL AVIATION

New Delhi, the 26th June, 2018

S.O. 1032.—In pursuance of Sub-rule (4) of Rule 10 of the Official Languages (Use for Official Purpose of the Union) Rules, 1976, the Central Government hereby notifies the Office of The Airport Director, Airports Authority of India, Mysore Airport, Mysore (Karnataka), where 80% staff have acquired the working knowledge of Hindi.

[No. E-11014/9/2015-OL]

S. K. MISHRA, Jt. Secy.

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

नई दिल्ली, 28 जून, 2018

का.आ. 1033.—केन्द्रीय सरकार, राजभाषा (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग) नियम, 1976 के नियम 10 के उपनियम (4) के अनुसरण में, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के निम्नलिखित कार्यालयों को, जिनके 80 या अधिक प्रतिशत कर्मचारीवृन्द ने हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है, अधिसूचित करती है :-

1. हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड,
हिसार क्षेत्रीय कार्यालय,
दूसरी मंजिल, एस.जे. टावर, सेक्टर 13,
हिसार-तोशाम रोड,
हिसार-125005

[सं. 11011/1/2017 (हिंदी)]

ऊषा बिन्जोला, संयुक्त निदेशक (राजभाषा)

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

New Delhi, the 28th June, 2018

S.O. 1033.—In pursuance of Sub-rule (4) of Rule 10 of the Official Language (Use for Official Purpose of the Union) Rules, 1976, the Central Government hereby notifies the following offices of the Public Sector Undertakings under the administrative control of the Ministry of Petroleum and Natural Gas in which 80 or more per cent of the staff have acquired the working knowledge of Hindi :

1. Hindustan Petroleum Corporation Ltd.,
Hisar Regional Office,
2nd Floor, S.J. Tower, Sector 13,
Hisar Tosham Road, Hisar-125005

[No. 11011/1/2017 (Hindi)]

USHA BINJOLA, Jt. Director (OL)

नई दिल्ली, 3 जुलाई, 2018

का.आ. 1034.—केन्द्रीय सरकार ने पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उप-धारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना, जिसका प्रकाशन भारत के राजपत्र संख्या 10, दिनांक 17.03.2018 का. आ संख्या 437 दिनांक 26.02.2018 भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (ii) में किया गया है। इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट हिमाचल राज्य की तहसील उना तथा हरोली, जिला उना की भूमि में, पंजाब राज्य में गाँव : झुगियां, जिला शहीद भगत सिंह नगर से हिमाचल प्रदेश के गाँव : पेखुवेला, जिला उना तक पेट्रोलियम उत्पादों के परिवहन के लिए इंडियन ऑइल कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा पीएजेपीएल – उना ब्रांच पाइपलाइन परियोजना के सम्बंध में पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के लिए अपने आशय की घोषणा की थी।

और उक्त राजपत्र अधिसूचनाओं की प्रतियाँ जनता को तारीख 14.05.2018 तक उपलब्ध करा दी गई थी।

और उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अनुसरण में सक्षम प्राधिकारी ने केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है।

और केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात और यह समाधान हो जाने पर कि उक्त भूमि पाइपलाइन बिछाने के लिए अपेक्षित है, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने का विनिश्चय किया है।

अतः अब, केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए घोषणा करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में पाइपलाइन बिछाने के उपयोग का अधिकार अर्जित किया जाए।

और केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निर्देश देती है कि उक्त भूमि में उपयोग का अधिकार इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख से केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर इंडियन ऑइल कार्पोरेशन लिमिटेड में निहित होगा।

पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन अधिनियम, 1962 की धारा 10 के अधीन किसी भी क्षतिपूर्ति के लिए इंडियन ऑइल कार्पोरेशन लिमिटेड पूर्णतया उत्तरदायी होगी और पाइपलाइन से सम्बन्धित किसी भी मामले पर केन्द्रीय सरकार के विरुद्ध कोई वाद - दावा या कानूनी कार्यवाही नहीं हो सकेगी।

अनुसूची

जिला: उना

राज्य : हिमाचल प्रदेश

क्र. सं.	तहसील का नाम	गाँव का नाम	हदबस्त नं	खसरा सं.	क्षेत्रफल		
					हेक्टेयर	एयर	वर्ग मीटर
1	2	3	4	5	6	7	8
1	हरोली	बाथडी	476	1069	00	00	68
				1076	00	06	49
				1077	00	01	84

				1081	00	02	71
				1133	00	17	59
				1134	00	00	67
				1131	00	05	24
				1130	00	02	78
				1129/4	00	01	30
				1129/3	00	00	20
				1124/4	00	04	62
				1124/3	00	01	00
				1124/2	00	00	94
				1124/1	00	00	98
				1121	00	09	24
				1116	00	23	32
				929	00	04	12
				59	00	00	20
				121	00	00	20
				126	00	00	20
				135	00	00	60
				133	00	00	58
				125	00	03	77
2	हरोली	केलुवा		3058	00	00	20
				2945	00	00	20
				2890	00	00	20
				3068	00	00	45
				3061	00	00	36
				3129	00	04	48
				3127	00	00	26
				2643/1	00	00	20
				2643/2	00	00	41
				2953/1	00	01	48
				2953/2	00	02	27
				3128	00	05	32
				2611	00	00	90
3	हरोली	बाथू	475	1558	00	01	03

				1565	00	00	20
				1895	00	00	32
				1677	00	00	77
4	हरोली	बटखुर्द	474	1458	00	00	20
				1316	00	01	68
				1689	00	00	98
				1695	00	00	20
				1290	00	00	45
				1468	00	00	87
5	हरोली	टहलीवाल उपरला	472	415	00	00	20
6	हरोली	मनुवाल	471	2673	00	00	75
7	हरोली	थेह	471	2129	00	02	82
8	उना	उदयपुर	224	1205	00	00	20
9	उना	नंगड़ा ज़िला	222	1829	00	09	48
				1674	00	03	64
				1675	00	00	20
				1281	00	00	68
				273	00	04	34
				1664	00	00	20
				1181	00	15	66
				571	00	00	20
				363	00	02	74
				2266/515	00	01	55
				2267/515	00	01	82
				1668	00	00	20
10	उना	पेखूवेला		1009	00	03	96
				1007	00	06	58
				1008	00	09	87
				1004	00	00	20
				1011	00	05	55
				1018	00	04	40
				1015	00	06	85
				1016	00	18	07

New Delhi, the 3rd July, 2018

S.O. 1034.—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas, published in the Gazette No. 10, dated 17.03.2018, S.O. No. 437, dated 26.02.2018 Part-II, section 3, sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), (hereinafter referred to as the said Act) the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the land situated in Tehsil Una and Haroli of District Una in Himachal Pradesh State, specified in the Schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline for the transportation of petroleum product from village Jhungian, District Shahid Bhagat Singh Nagar in the State of Punjab to village Pekhubela, District Una in the State of Himachal Pradesh by the Indian Oil Corporation Limited for implementing the "PAJPL - Una Branch Pipeline project".

And whereas the copies of the said Gazette notification were made available to the public on 14.05.2018.

And whereas the Competent Authority has under sub-section (1) of section 6 of the said Act, has submitted his report of Central Government.

And whereas, the Central Government after considering the said report and on being satisfied that the said land is required for laying the pipeline, has decided to acquire right of the user therein;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the land specified in the Schedule appended to this notification is hereby acquired for laying the pipeline.

And further, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 6 of the said Act, the Central Government hereby directs that the right of user of the said land for laying the pipeline shall, instead of vesting in the Central Government, vests on the date of publication of the declaration, in India Oil Corporation Limited, free from all encumbrances.

India Oil Corporation Limited shall be exclusively liable for any compensation in terms of section 10 of the P & MP Act, 1962 and no suit, claim or legal proceeding would lie against the Central Government on any matter relating to pipeline.

SCHEDULE

District : Una

State : Himachal Pradesh

Sr. No.	Name of Tehsil	Name of Village	Hadbast No.	Khasara No.	Area		
					Hectare	Are	Sq. mtr.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Haroli	Bathari	476	1069	00	00	68
				1076	00	06	49
				1077	00	01	84
				1081	00	02	71
				1133	00	17	59
				1134	00	00	67
				1131	00	05	24
				1130	00	02	78
				1129/4	00	01	30
				1129/3	00	00	20
				1124/4	00	04	62
				1124/3	00	01	00
				1124/2	00	00	94
				1124/1	00	00	98
				1121	00	09	24
				1116	00	23	32
				929	00	04	12

				59	00	00	20
				121	00	00	20
				126	00	00	20
				135	00	00	60
				133	00	00	58
				125	00	03	77
2	Haroli	Keluwa		3058	00	00	20
				2945	00	00	20
				2890	00	00	20
				3068	00	00	45
				3061	00	00	36
				3129	00	04	48
				3127	00	00	26
				2643/1	00	00	20
				2643/2	00	00	41
				2953/1	00	01	48
				2953/2	00	02	27
				3128	00	05	32
				2611	00	00	90
3	Haroli	Bathu	475	1558	00	01	03
				1565	00	00	20
				1895	00	00	32
				1677	00	00	77
4	Haroli	Bat Khurd	474	1458	00	00	20
				1316	00	01	68
				1689	00	00	98
				1695	00	00	20
				1290	00	00	45
				1468	00	00	87
5	Haroli	Tahliwal Upparla	472	415	00	00	20
6	Haroli	Manuwal	471	2673	00	00	75
7	Haroli	Theh	471	2129	00	02	82
8	Una	Udaypur	224	1205	00	00	20
9	Una	Nangran Jhikla	222	1829	00	09	48
				1674	00	03	64
				1675	00	00	20
				1281	00	00	68
				273	00	04	34
				1664	00	00	20
				1181	00	15	66
				571	00	00	20

			363	00	02	74
			2266/515	00	01	55
			2267/515	00	01	82
			1668	00	00	20
10	Una	Pekhubela	1009	00	03	96
			1007	00	06	58
			1008	00	09	87
			1004	00	00	20
			1011	00	05	55
			1018	00	04	40
			1015	00	06	85
			1016	00	18	07

[F. No. R-11025(11)/248/2017-OR-I/E-18228]

PAWAN KUMAR, Under Secy.

नई दिल्ली, 3 जुलाई, 2018

का.आ. 1035.—केन्द्रीय सरकार ने पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उप-धारा (1) के अधीन जारी की गई, भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 1959 तारीख 21.08.2017 जिसका प्रकाशन भारत के राजपत्र संख्या 34, भाग-II, खण्ड 3, उप-खण्ड (ii) तारीख 26.08.2017 में किया गया है। इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट ओडिशा राज्य के तहसील : **ओडगाँव**, जिला : **नयागढ़** की भूमि में, ओडिशा राज्य में पारादीप से तेलंगाना राज्य में हैदराबाद तक पेट्रोलियम उत्पादों के परिवहन के लिये इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा क्रियान्वित किए जा रहे "पारादीप-हैदराबाद पाइपलाइन परियोजना" के संबंध में पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिये उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के लिये अपने आशय की घोषणा की थी;

और उक्त राजपत्र अधिसूचना की प्रतियाँ जनता को उपलब्ध करा दी गई थीं। और उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अनुसरण में सक्षम प्राधिकारी ने केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है;

और केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात और यह समाधान हो जाने पर कि उक्त भूमि पाइपलाइन बिछाने के लिये अपेक्षित है, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने का विनिश्चय किया है;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद् द्वारा घोषणा करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में पाइपलाइन बिछाने के उपयोग का अधिकार अर्जित किया जाए; और केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निर्देश देती है कि उक्त भूमि में उपयोग का अधिकार इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख से केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाए सभी बिल्लिंगमों से मुक्त होकर इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड में निहित होगा।

अनुसूची

तहसील - ओडगाँव	जिला - नयागढ़	राज्य - ओडिशा		
गाँव का नाम	प्लॉट नं.		क्षेत्रफल	
		हेक्टर	एयर	वर्ग मीटर
1	2	3	4	5
गोडिपड़ा	103/2278	00	04	19
जागिरि खडरपट्टि	258	00	02	26
	255	00	02	52

	252	00	00	24
	9	00	04	33
	62	00	03	34
	61	00	01	45
	61/948	00	00	72
	64	00	02	12
मझिआँखण्ड	602/1533	00	05	76
	618	00	03	93
	608	00	03	37
	767	00	04	84
	767/1608	00	02	41
भालिआडिही	1475	00	07	51
	1479	00	03	35
	171	00	06	83
	163	00	02	37
गोलगाँ	1306	00	03	48
	1233	00	07	30
धुसुमा	1520	00	06	78
	1517	00	00	39
	1517/1864	00	00	67
	1514/1753	00	00	54
	1525	00	02	49
	1513	00	02	51
	624	00	06	97
	609	00	04	40
	606	00	02	60
	585	00	00	10
	579	00	00	10
	580	00	05	77
शिखर पुर	912	00	02	92

	841	00	04	28
	779	00	00	13
	787	00	00	49
	698	00	05	31
	560	00	07	86
	553	00	05	23
	2916	00	00	10
	2949	00	00	91
	2966	00	01	20
	2970	00	06	30
	3008	00	05	88
	3019	00	05	37
	3019/4834	00	02	28
असुरढिपा	758	00	00	34
	805	00	08	44
	798	00	00	10
	798/1323	00	00	10
हरिहरपुर	1862	00	01	99
	1853	00	01	69
	1854	00	00	19
	1854/2669	00	01	10
	1001	00	03	94
	1001/2380	00	03	52
	924	00	04	17
	898	00	05	48
	878/2383	00	02	80
	878/2204	00	02	42
	1054/2361	00	00	97
	1067/2379	00	00	88
	1067	00	05	16

	1068	00	00	10
करझारघुनाथपुर	435	00	03	83
	432	00	04	35
	432/790	00	02	72
	334	00	00	38
	339	00	05	09
	321	00	00	26
	321/833	00	00	42
	321/844	00	00	93
	321/845	00	01	00
	321/846	00	01	01
	321/847	00	00	84
	120	00	01	84
	65	00	02	29
	66	00	02	73
	73	00	00	42
बड़पुट	647	00	00	10
	419	00	01	69
	426	00	04	69
	343/1832	00	02	73
	302	00	02	62
महुलिया	1036	00	01	22
	1036/1662	00	02	58
	477	00	00	79
	477/1462	00	08	87
नन्दिघोर	2596	00	11	96
	2567	00	00	10
	2566	00	00	10
	2566/4584	00	00	10
	2557	00	07	87

	2554	00	01	56
	2551	00	00	10
	2551/4585	00	00	10
	2545	00	03	43
	2540	00	02	58
	2535	00	01	33
	2508	00	06	08
	399	00	08	76
ओस्तिआ	144	00	01	83
रगडिमडा	592/757	00	03	00
	527/711	00	03	67
	125	00	00	25
	125/763	00	00	30
	125/764	00	00	25
	127	00	10	14
	132	00	05	32
गुन्डासाहि	986	00	12	82
	455	00	02	34
	453	00	01	15
	442	00	00	64
	447	00	07	02
	307	00	06	16
	325	00	03	53
	325/1026	00	05	53
	326	00	00	10
	347	00	04	04
	256	00	05	61
कोरपिठा	575	00	13	53
	541	00	08	66
	541/1491	00	01	16

	542	00	06	99
	529	00	01	60
	528	00	01	12
	549	00	06	05
	523	00	02	89
	524	00	01	64
	421	00	01	30
	423	00	09	34
सरमरेइसाहि	566	00	05	59
	225	00	29	52
	232	00	08	43
	233	00	04	90
	116/539	00	05	79
	116/540	00	20	85
	116/538	00	06	19
कइबलपुर	304	00	00	87
	314	00	00	17
	314/794	00	00	21
	311	00	01	13
	97	00	00	96
	97/709	00	00	96
	96	00	03	57
	73	00	04	66
	19	00	02	71
रबिगाड़िआ	313	00	03	76
	320	00	01	78
	315	00	11	31
	316	00	01	13
	215	00	08	25
	215/426	00	04	35

	217	00	01	42
कुरुमबाकंतरा	1104	00	02	50
	1130	00	03	99
	1130/2379	00	02	14
गोदरकणा	46	00	02	03
	46/79	00	02	06
	46/80	00	02	07
	41	00	06	23
देओगाँ	453	00	00	10
	455	00	00	55
	771/1442	00	02	45
	1319	00	01	66
कुराल	3995	00	13	38
	4004	00	00	91
	4038	00	04	11
	4034	00	29	78
	4092	00	03	32
	4097	00	03	22
	4096/4489	00	01	08
	4102	00	08	76
	4243	00	04	95
	4238	00	04	41
	4224	00	07	18
	4162/4590	00	03	19
	4590	00	03	19
	4175	00	00	10
	4178	00	04	77
	3056	00	07	57
	2812	00	00	85
हनुमन्तिआ	242	00	00	10

	242/1416	00	00	10
	242/1218	00	04	38
	270	00	00	83
	270/1412	00	00	46
	1166	00	00	84
नाउरिआगोड़ा	471	00	03	58
	473	00	01	83
	472	00	00	44
	470	00	00	57
	188	00	01	59
	189	00	00	87

[फा. सं. आर-11025(11)/236/2017-ओआर-I/ई-13717]

पवन कुमार, अवर सचिव

New Delhi, the 3rd July, 2018

S.O. 1035.—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas, published in the Gazette of India No. 34 Part-II, Section 3, Sub-section (ii) dated 26.08.2017 vide S.O. Number 1959 dated 21.08.2017 issued under Sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), (hereinafter referred to as the said Act) the Central Government declared its intension to acquire the right of user in the land situted in Tehsil-Odagaon, District-Nayagarh in Odisha State, specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline for the transportation of petroleum products from Paradip in the State of Odisha to Hyderabad in the State of Telengana by the Indian Oil Corporation Limited for implementing the “Paradip-Hyderabad Pipeline Project”.

And whereas the copies of the Gazette were made available to the public. And whereas the Competent Authority has under Sub-section (1) of section 6 of the said Act, has submitted his report of Central Government;

And whereas, the Central Government after considering the said report and on being satisfied that the said land is required for laying the pipeline, has decided to acquire right of the user therein;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the land specified in the schedule appended to this notification is hereby acquired for laying the pipeline;

And further, in exercise of the powers conferred by Sub-section (4) of Section 6 of the said Act, the Central Government hereby directs that the right of user of the said land for laying the pipeline shall, instead of vesting in the Central Government, vests on the date of publication of the declaration, in Indian Oil Corporation Limited, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Tehsil : ODAGAON	District : NAYAGARH	State : ODISHA		
Name of the Village	Plot No.	Area		
		Hectare	Are	Sq.mtr.
1	2	3	4	5
GODIPARA	103/2278	00	04	19
JAGIRIKHAIRPATI	258	00	02	26

	255	00	02	52
	252	00	00	24
	9	00	04	33
	62	00	03	34
	61	00	01	45
	61/948	00	00	72
	64	00	02	12
MAJHIKHAND	602/1533	00	05	76
	618	00	03	93
	608	00	03	37
	767	00	04	84
	767/1608	00	02	41
BHALIADIHI	1475	00	07	51
	1479	00	03	35
	171	00	06	83
	163	00	02	37
GOLGAN	1306	00	03	48
	1233	00	07	30
DHUSUMA	1520	00	06	78
	1517	00	00	39
	1517/1864	00	00	67
	1514/1753	00	00	54
	1525	00	02	49
	1513	00	02	51
	624	00	06	97
	609	00	04	40
	606	00	02	60
	585	00	00	10
	579	00	00	10
	580	00	05	77
SIKHAR PUR	912	00	02	92
	841	00	04	28
	779	00	00	13
	787	00	00	49
	698	00	05	31
	560	00	07	86
	553	00	05	23
	2916	00	00	10
	2949	00	00	91
	2966	00	01	20

	2970	00	06	30
	3008	00	05	88
	3019	00	05	37
	3019/4834	00	02	28
ASURDHIPA	758	00	00	34
	805	00	08	44
	798	00	00	10
	798/1323	00	00	10
HARIHARPUR	1862	00	01	99
	1853	00	01	69
	1854	00	00	19
	1854/2669	00	01	10
	1001	00	03	94
	1001/2380	00	03	52
	924	00	04	17
	898	00	05	48
	878/2383	00	02	80
	878/2204	00	02	42
	1054/2361	00	00	97
	1067/2379	00	00	88
	1067	00	05	16
	1068	00	00	10
KARADARAGHUNATHPUR	435	00	03	83
	432	00	04	35
	432/790	00	02	72
	334	00	00	38
	339	00	05	09
	321	00	00	26
	321/833	00	00	42
	321/844	00	00	93
	321/845	00	01	00
	321/846	00	01	01
	321/847	00	00	84
	120	00	01	84
	65	00	02	29
	66	00	02	73
	73	00	00	42
BARPUT	647	00	00	10
	419	00	01	69
	426	00	04	69

	343/1832	00	02	73
	302	00	02	62
MAHULIA	1036	00	01	22
	1036/1662	00	02	58
	477	00	00	79
	477/1462	00	08	87
NANDIGHORE	2596	00	11	96
	2567	00	00	10
	2566	00	00	10
	2566/4584	00	00	10
	2557	00	07	87
	2554	00	01	56
	2551	00	00	10
	2551/4585	00	00	10
	2545	00	03	43
	2540	00	02	58
	2535	00	01	33
	2508	00	06	08
	399	00	08	76
OSTIA	144	00	01	83
RAGARIMARA	592/757	00	03	00
	527/711	00	03	67
	125	00	00	25
	125/763	00	00	30
	125/764	00	00	25
	127	00	10	14
	132	00	05	32
GUNTHASAH	986	00	12	82
	455	00	02	34
	453	00	01	15
	442	00	00	64
	447	00	07	02
	307	00	06	16
	325	00	03	53
	325/1026	00	05	53
	326	00	00	10
	347	00	04	04
	256	00	05	61
KORPITHA	575	00	13	53
	541	00	08	66

	541/1491	00	01	16
	542	00	06	99
	529	00	01	60
	528	00	01	12
	549	00	06	05
	523	00	02	89
	524	00	01	64
	421	00	01	30
	423	00	09	34
SARMAREISAH	566	00	05	59
	225	00	29	52
	232	00	08	43
	233	00	04	90
	116/539	00	05	79
	116/540	00	20	85
	116/538	00	06	19
KAIBALPUR	304	00	00	87
	314	00	00	17
	314/794	00	00	21
	311	00	01	13
	97	00	00	96
	97/709	00	00	96
	96	00	03	57
	73	00	04	66
	19	00	02	71
RABIGARIA	313	00	03	76
	320	00	01	78
	315	00	11	31
	316	00	01	13
	215	00	08	25
	215/426	00	04	35
	217	00	01	42
KURUMBANKTARA	1104	00	02	50
	1130	00	03	99
	1130/2379	00	02	14
GODARKANA	46	00	02	03
	46/79	00	02	06
	46/80	00	02	07
	41	00	06	23
DEOGAN	453	00	00	10

	455	00	00	55
	771/1442	00	02	45
	1319	00	01	66
KURAL	3995	00	13	38
	4004	00	00	91
	4038	00	04	11
	4034	00	29	78
	4092	00	03	32
	4097	00	03	22
	4096/4489	00	01	08
	4102	00	08	76
	4243	00	04	95
	4238	00	04	41
	4224	00	07	18
	4162/4590	00	03	19
	4590	00	03	19
	4175	00	00	10
	4178	00	04	77
	3056	00	07	57
	2812	00	00	85
HANUMANTIA	242	00	00	10
	242/1416	00	00	10
	242/1218	00	04	38
	270	00	00	83
	270/1412	00	00	46
	1166	00	00	84
NAURIAGORA	471	00	03	58
	473	00	01	83
	472	00	00	44
	470	00	00	57
	188	00	01	59
	189	00	00	87

[F. No. R-11025(11)/236/2017-OR-I/E-13717]

PAWAN KUMAR, Under Secy.

नई दिल्ली, 3 जुलाई, 2018

का.आ. 1036.—केन्द्रीय सरकार ने पेट्रोलियम एवं खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उप धारा (1) के अधीन जारी की गई, भारत सरकार के पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 1813 तारीख 03.08.2017 जिसका

प्रकाशन भारत के राजपत्र संख्या 32, भाग-II, खण्ड 3, उप-खण्ड (ii) तारीख 12.08.2017 में किया गया है, द्वारा उस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट ओडिशा राज्य के तहसील : पिपिलि, जिला : पुरी की भूमि में, ओडिशा राज्य में पारादीप से तेलंगाना राज्य में हैदराबाद तक पेट्रोलियम उत्पादों के परिवहन के लिये इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा क्रियान्वित किए जा रहे "पारादीप-हैदराबाद पाइपलाइन परियोजना" के संबंध में पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिये उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के लिये अपने आशय की घोषणा की थी;

और उक्त राजपत्र अधिसूचना की प्रतियाँ जनता को उपलब्ध करा दी गई थीं। और उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अनुसरण में सक्षम प्राधिकारी ने केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है। और केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात और यह समाधान हो जाने पर कि उक्त भूमि पाइपलाइन बिछाने के लिये अपेक्षित है, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने का विनिश्चय किया है।

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा घोषणा करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में पाइपलाइन बिछाने के उपयोग का अधिकार अर्जित किया जाता है।

और केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निर्देश देती है कि उक्त भूमि में उपयोग का अधिकार, इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख से, केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाए सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड में निहित होगा;

अनुसूची

तहसील- पिपिलि	जिला - पुरी	राज्य - ओडिशा		
गाँव का नाम	प्लॉट नं.	क्षेत्रफल		
		हेक्टर	एयर	वर्ग मीटर
1	2	3	4	5
सिउला	238	00	09	38
	85	00	03	99
	246	00	03	75
मकरबा	96	00	08	54
भारतीपुर	1550	00	08	09
बागेश्वरपुर	769	00	10	09

[फा. सं. आर-11025(11)/236/2017-ओआर-I/ई-13717]

पवन कुमार, अवर सचिव

New Delhi, the 3rd July, 2018

S.O. 1036.—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas, published in the Gazette of India No. 32, Part-II, Section 3, Sub-section (ii) dated 12.08.2017 vide S.O. Number 1813 dated 03.08.2017 issued under Sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962) hereinafter referred to as the said Act, the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the land situated in Tehsil- Pipili, District-Puri in Odisha State, specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline for the transportation of petroleum products from Paradip in the State of Odisha to Hyderabad in the State of Telangana by Indian Oil Corporation Limited for implementing the "Paradip-Hyderabad Pipeline Project".

And whereas the copies of the Gazette were made available to the public, And whereas the Competent Authority has under Sub-section (1) of section 6 of the said Act, has submitted his report to the Central Government;

And whereas, the Central Government after considering the said report and on being satisfied that the said land is required for laying the pipeline, has decided to acquire right of the user in the land specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the land specified in the schedule appended to this notification is hereby acquired for laying the pipeline;

And further, in exercise of the powers conferred by Sub-section (4) of Section 6 of the said Act, the Central Government hereby directs that the right of user in the said land for laying the pipeline shall, instead of vesting in the Central Government, vests on the date of publication of the declaration, in Indian Oil Corporation Limited, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Tehsil : PIPILI	District : PURI	State : ODISHA		
Name of the Village	Plot No.	Area		
		Hectare	Are	Sq.mtr.
1	2	3	4	5
SIULA	238	00	09	38
	85	00	03	99
	246	00	00	75
MAKARABA	96	00	08	54
BHARATIPUR	1550	00	08	09
BAGESWARPUR	769	00	10	09

[F. No. R-11025(11)/236/2017-OR-I/E-13717]

PAWAN KUMAR, Under Secy.

नई दिल्ली, 3 जुलाई, 2018

का.आ. 1037.—केन्द्रीय सरकार ने पेट्रोलियम एवं खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उप धारा (1) के अधीन जारी की गई, भारत सरकार के पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 1816 तारीख 03.08.2017 जिसका प्रकाशन भारत के राजपत्र संख्या 32, भाग-II, खण्ड 3, उप-खण्ड (ii) तारीख 12.08.2017 में किया गया है, द्वारा उस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट ओडिशा राज्य के तहसील : टांगि, जिला : खोर्द्धा की भूमि में, ओडिशा राज्य में पारादीप से तेलंगाना राज्य में हैदराबाद तक पेट्रोलियम उत्पादों के परिवहन के लिये इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा क्रियान्वित किए जा रहे "पारादीप-हैदराबाद पाइपलाइन परियोजना" के संबंध में पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिये उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के लिये अपने आशय की घोषणा की थी;

और उक्त राजपत्र अधिसूचना की प्रतियाँ जनता को उपलब्ध करा दी गई थीं। और उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अनुसरण में सक्षम प्राधिकारी ने केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है। और केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात और यह समाधान हो जाने पर कि उक्त भूमि पाइपलाइन बिछाने के लिये अपेक्षित है, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने का विनिश्चय किया है।

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा घोषणा करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में पाइपलाइन बिछाने के उपयोग का अधिकार अर्जित किया जाता है।

और केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निर्देश देती है कि उक्त भूमि में उपयोग का अधिकार, इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख से, केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाए सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड में निहित होगा;

अनुसूची

तहसील- टांगि	जिला - खोर्द्धा	राज्य -ओड़िशा		
गाँव का नाम	प्लॉट नं.	क्षेत्रफल		
		हेक्टर	एयर	वर्ग मीटर
1	2	3	4	5
खजुरिआ	305	00	00	67
	308	00	06	31
	503	00	02	96
	321	00	04	18
	321/653	00	07	06
डमणभूई	1859	00	17	19
	1856	00	03	08
असुरद्विप	281/396	00	00	94
	19	00	02	75

[फा. सं. आर-11025(11)/236/2017-ओआर-I/ई-13717]

पवन कुमार, अवर सचिव

New Delhi, the 3rd July, 2018

S.O. 1037.—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas, published in the Gazette of India No. 32,Part-II, Section 3, Sub-section (ii) dated 12.08.2017 vide S.O. Number 1816 dated 03.08.2017 issued under Sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962) hereinafter referred to as the said Act, the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the land situated in Tehsil- Tangi, District-Khordha in Odisha State, specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline for the transportation of petroleum products from Paradip in the State of Odisha to Hyderabad in the State of Telangana by Indian Oil Corporation Limited for implementing the “Paradip-Hyderabad Pipeline Project”.

And whereas the copies of the Gazette were made available to the public, And whereas the Competent Authority has under Sub-section (1) of section 6 of the said Act, has submitted his report to the Central Government;

And whereas, the Central Government after considering the said report and on being satisfied that the said land is required for laying the pipeline, has decided to acquire right of the user in the land specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the land specified in the schedule appended to this notification is hereby acquired for laying the pipeline;

And further, in exercise of the powers conferred by Sub-section (4) of Section 6 of the said Act, the Central Government hereby directs that the right of user in the said land for laying the pipeline shall, instead of vesting in the Central Government, vests on the date of publication of the declaration, in Indian Oil Corporation Limited, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Tehsil : TANGI	District : KHORDHA	State : ODISHA		
Name of the Village	Plot No.	Area		
		Hectare	Are	Sq.mtr.
1	2	3	4	5
KHAJURIA	305	00	00	67
	308	00	06	31
	503	00	02	96
	321	00	04	18
	321/653	00	07	06
DAMANBHUIN	1859	00	17	19
	1856	00	03	08
ASURADHIPA	281/396	00	00	94
	19	00	02	75

[F. No. R-11025(11)/236/2017-OR-I/E-13717]

PAWAN KUMAR, Under Secy.

नई दिल्ली, 3 जुलाई, 2018

का.आ. 1038.—केन्द्रीय सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि पारादीप (ओड़िशा) से हैदराबाद (तेलंगाना) तक पेट्रोलियम उत्पादों के परिवहन के लिए इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा "पारादीप-हैदराबाद पाइपलाइन" बिछाई जानी चाहिए;

और केन्द्रीय सरकार को ऐसी पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि ऐसी भूमि में जो इस से उपाबद्ध अनुसूची में वर्णित है और जिस में उक्त पाइपलाइन बिछाए जाने का प्रस्ताव है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन्स (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उस भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है;

कोई व्यक्ति, जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको इस अधिसूचना से युक्त भारत के असाधारण राजपत्र की प्रतियाँ साधारण जनता को उपलब्ध करा दी जाती है, इक्कीस दिन के भीतर भूमि के नीचे पाइपलाइन बिछाए जाने के लिए उस में उपयोग के अधिकार के अर्जन के सम्बन्ध में श्री दिल्लीप कुमार महांति, सक्षम प्राधिकारी, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, पारादीप-हैदराबाद पाइपलाइन परियोजना, तृतीय तल, आलोक भारती टावर, शहीद नगर, भुवनेश्वर -751007, ओड़िशा को लिखित रूप में आक्षेप भेज सकेगा।

अनुसूची

राज्य - ओड़िशा							
क्र. सं.	जिला	तहसील	गाँव का नाम	प्लॉट नं.	क्षेत्रफल		
					हेक्टेयर	एयर	वर्ग मीटर
1	2	3	4	5	6	7	8
1	गंजाम	आसिका	कुम्भारी	3459	0	0	50
				3463	0	3	22

				3469	0	5	63
				3733	0	5	36
				3470	0	2	1
				3474	0	2	21
				3472	0	0	93
				3473	0	2	25
				3880	0	0	35
				3879	0	5	26
				3881	0	1	19
				3882	0	4	99
				3876	0	5	51
2	गंजाम	आसिका	भेंकटराइपली	130	0	4	37
				153	0	1	77
				154	0	1	7
				152	0	2	69
				150	0	1	30
				151	0	1	20
				149	0	2	30
				148	0	1	71
				147	0	0	10
				142	0	2	96
				378	0	2	4
				377	0	3	56
				376	0	0	10
				357	0	0	74
				358	0	2	45
3	गंजाम	शेरगढ़	पुनान्द	881	0	4	45
				882	0	3	7
				950	0	5	20
				1242	0	0	10

				657	0	0	74
4	गंजाम	शेरगढ़	किर्तिपुर	1245	0	5	39
				1240	0	3	23
				1244	0	5	29
				1241	0	2	37
				1242	0	7	43
				1238	0	0	25
				1237	0	6	31
				1236	0	7	1
				1231	0	1	13
				1220	0	4	97
				1222	0	5	93
				1223	0	5	40
				1224	0	4	32
				1071	0	6	48
	गंजाम	शेरगढ़	किर्तिपुर	1210	0	5	40
				1208	0	1	80
				1203	0	0	72
				1207	0	8	73
				1205	0	18	44
				1155	0	28	44
				1153	0	5	76
5	गंजाम	बुगुडा	बिरंचिपुर	422	0	0	19
				424	0	0	25
				3118	0	0	19
				3119	0	3	47
				3127	0	1	77
				3124	0	0	50
				3121	0	1	14
				3122	0	1	2

				3123	0	0	33
				3117	0	1	99
				3113	0	9	1
				3112	0	0	83
				3102	0	0	88
				3103	0	4	20
				11875	0	4	4
				3104	0	5	15
	गंजाम	बुगुड़ा	बिरंचिपुर	1060	0	2	75
				1061	0	1	85
6	गंजाम	बुगुड़ा	नगुडु	2407	0	0	90
7	गंजाम	हिंजिलिकाटु	पोचिलिमा	1694	0	0	14
8	गंजाम	हिंजिलिकाटु	मकरझोल	4458	0	3	99
				4948	0	1	23
				6384	0	2	45
9	गंजाम	जगन्नाथप्रसाद	चढैयापल्ली	2660	0	3	2
				7261	0	2	74
10	गंजाम	पात्रपुर	सरधापुर	1294	0	2	34
11	गंजाम	पोलसरा	केन्दुबाडि	7090	0	0	33
				7290	0	1	10
				7295	0	0	26
12	गंजाम	कुकुडाखण्डी	महुधराहिल	98	0	6	40
				99	0	12	67
13	गंजाम	कुकुडाखण्डी	भगवानपुर	590	0	0	40
14	पुरी	डेलंग	बसन्तपुर	447	0	6	93
				524	0	0	30
				525	0	0	47
				528	0	4	38
15	पुरी	डेलंग	रेंगल	3200	0	0	30
				3201	0	2	38

	पुरी	डेलांग	रेंगल	3202	0	1	60
				3320	0	0	21
				3318	0	4	15
				3327	0	1	22
				3326	0	10	45
				3328	0	9	30
				3351	0	1	52
				3350	0	3	98
				3346	0	5	91
				3347	0	5	70
				3343	0	6	39
				3415	0	1	72
				3503	0	0	46
				3505	0	0	12
				3551	0	1	1
				3550	0	0	53
				3528	0	2	23
				3529	0	1	54
				3547	0	2	46
				3531	0	6	42
				3546	0	5	50
				3538	0	2	31
				3532	0	4	53
				3536	0	1	62
	पुरी	डेलांग	रेंगल	3535	0	1	35
16	पुरी	पिपिलि	सिउला	206	0	2	20
				228	0	0	30

[फा. सं. आर-11025(11)/236/2017-ओआर-I/ई-13717]

पवन कुमार, अवर सचिव

New Delhi, the 3rd July, 2018

S.O. 1038.—Whereas, it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transportation of petroleum products from Paradip (Odisha) to Hyderabad (Telangana), “Paradip-Hyderabad Pipeline” should be laid by Indian Oil Corporation Limited;

And whereas, it appears to the Central Government that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in land under which the said pipeline is proposed to be laid and which is described in the schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Any person interested in the land described in the said schedule may, within twenty-one days from the date on which copies of the Extraordinary Gazette of India containing this notification are made available to the general public, object in writing to the acquisition of the right of user therein for laying of the pipeline under the land to Sri Dillip Kumar Mohanty, Competent Authority, Indian Oil Corporation Limited, Paradip-Hyderabad Pipeline Project, 3rd Floor, Alok Bharati Tower, Saheed Nagar, Bhubaneswar- 751007, (Odisha).

SCHEDULE

State - Odisha							
Sl.No.	District	Tahasil	Village	Plot No.	Area		
					Hectare	Are	Sq.Mtr.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	GANJAM	ASKA	KUMBHARI	3459	00	00	50
				3463	00	03	22
				3469	00	05	63
				3733	00	05	36
				3470	00	02	01
				3474	00	02	21
				3472	00	00	93
				3473	00	02	25
				3880	00	00	35
				3879	00	05	26
				3881	00	01	19
				3882	00	04	99
				3876	00	05	51
2	GANJAM	ASKA	VENKATARAIPALLI	130	00	04	37
				153	00	01	77
				154	00	01	07
				152	00	02	69
				150	00	01	30
				151	00	01	20
				149	00	02	30
				148	00	01	71
				147	00	00	10
				142	00	02	96

				378	00	02	04
				377	00	03	56
	GANJAM	ASKA	VENKATARAIPALLI	376	00	00	10
				357	00	00	74
				358	00	02	45
3	GANJAM	SHERAGADA	PUNANDA	881	00	04	45
				882	00	03	07
				950	00	05	20
				1242	00	00	10
				657	00	00	74
4	GANJAM	SHERAGADA	KIRTIPUR	1245	00	05	39
				1240	00	03	23
				1244	00	05	29
				1241	00	02	37
				1242	00	07	43
				1238	00	00	25
				1237	00	06	31
				1236	00	07	01
				1231	00	01	13
				1220	00	04	97
				1222	00	05	93
				1223	00	05	40
				1224	00	04	32
				1071	00	06	48
				1210	00	05	40
				1208	00	01	80
				1203	00	00	72
	GANJAM	SHERAGADA	KIRTIPUR	1207	00	08	73
				1205	00	18	44
				1155	00	28	44
				1153	00	05	76
5	GANJAM	BUGUDA	BIRANCHIPUR	422	00	00	19
				424	00	00	25
				3118	00	00	19
				3119	00	03	47
				3127	00	01	77
				3124	00	00	50
				3121	00	01	14

				3122	00	01	02
				3123	00	00	33
				3117	00	01	99
				3113	00	09	01
				3112	00	00	83
				3102	00	00	88
				3103	00	04	20
				11875	00	04	04
				3104	00	05	15
				1060	00	02	75
				1061	00	01	85
6	GANJAM	BUGUDA	NAGUDU	2407	00	00	90
7	GANJAM	HINJILIKATU	POCHILIMA	1694	00	00	14
8	GANJAM	HINJILIKATU	MAKARAJHOL	4458	00	03	99
				4948	00	01	23
				6384	00	02	45
9	GANJAM	JAGANNATHPRASAD	CHADHEIAPALLI	2660	00	03	02
				7261	00	02	74
10	GANJAM	PATRAPUR	SARADHAPUR	1294	00	02	34
11	GANJAM	POLASARA	KENDUBADI	7090	00	00	33
				7290	00	01	10
				7295	00	00	26
12	GANJAM	KUKUDAKHANDI	MAHUGHARA HILL	98	00	06	40
				99	00	12	67
13	GANJAM	KUKUDAKHANDI	BHAGABANPUR	590	00	00	40
14	PURI	DELANG	BASANTPUR	447	00	06	93
				524	00	00	30
				525	00	00	47
				528	00	04	38
15	PURI	DELANG	RENGAL	3200	00	00	30
				3201	00	02	38
				3202	00	01	60
				3320	00	00	21
				3318	00	04	15
				3327	00	01	22
				3326	00	10	45
				3328	00	09	30
	PURI	DELANG	RENGAL	3351	00	01	52

				3350	00	03	98
				3346	00	05	91
				3347	00	05	70
				3343	00	06	39
				3415	00	01	72
				3503	00	00	46
				3505	00	00	12
				3551	00	01	01
				3550	00	00	53
				3528	00	02	23
				3529	00	01	54
				3547	00	02	46
				3531	00	06	42
				3546	00	05	50
				3538	00	02	31
				3532	00	04	53
				3536	00	01	62
				3535	00	01	35
16	PURI	PIPILI	SIULA	206	00	02	20
				228	00	00	30

[F. No. R-11025(11)/236/2017-OR-I/E-13717]

PAWAN KUMAR, Under Secy.

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

नई दिल्ली, 28 जून, 2018

का.आ. 1039.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार महाप्रबंधक, दूरसंचार जिला, बीएसएनएल, एलुरु, डब्ल्यूजी जिला एवं उनके कर्मचारी के प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण एवं श्रम न्यायालय, हैदराबाद के पंचाट (संदर्भ संख्या 14/2014) को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 29.05.2018 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल-40011/76/2013-आईआर (डीयू)]

राजेंद्र जोशी, उप निदेशक

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT

New Delhi, the 28th June, 2018

S.O. 1039.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award (I.D. No. 14/2014) of the Central Government Industrial Tribunal-cum-Labour Court, Hyderabad as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the General Manager, Telecom District, BSNL, Eluru, W.G. District and their workmen, which was received by the Central Government on 29.05.2018.

[No. L-40011/76/2013-IR (DU)]

RAJENDRA JOSHI, Dy. Director

ANNEXURE**BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT AT
HYDERABAD****Present :** Sri Muralidhar Pradhan, Presiding Officer

Dated : the 26th day of April, 2018

INDUSTRIAL DISPUTE No. 14/2014**Between :**The District Secretary,
National Union of BSNL Workers FNTU,
W.G. Distt. Eluru

...Petitioner

ANDThe General Manager,
Telecom District, BSNL,
Eluru, W.G. Distt.

...Respondent

Appearances :

For the Petitioner : Sri William Burra, Advocate

For the Respondent : Sri K. Ajay Kumar, Advocate

AWARD

The Government of India, Ministry of Labour by its order No. L- 40011/76/2013-IR(DU) dated 22.1.2014 referred the following dispute under section 10(1)(d) of the I.D. Act, 1947 for adjudication to this Tribunal between the management of Telecom District, BSNL, and their workmen. The reference is,

SCHEDULE

“Whether the demands of the workmen of BSNL, Eluru is legal and justified? If not, what other relief the workmen are entitled to?”

The reference is numbered in this Tribunal as I.D. No. 14/2014 and notices were issued to the parties concerned.

2. The case stands posted for Petitioner's evidence.

3. In spite of repeated calls, the Petitioner did not turn up. Several opportunities have been given to the Petitioner to attend the court to prosecute his case. But the Petitioner failed to attend this Tribunal which clearly indicates that perhaps the dispute of the Petitioner has already been settled and the Petitioner has got nothing to raise any claim against the Respondents. Hence, the case of the Petitioner is closed and a 'No dispute' award is passed.

Award is passed accordingly. Transmit.

Typed to my dictation by Smt. P. Phani Gowri, Personal Assistant, corrected by me on this the 26th day of April, 2018.

MURALIDHAR PRADHAN, Presiding Officer

Appendix of evidence

Witnesses examined for the Petitioner

NIL

Witnesses examined for the Respondent

NIL

Documents marked for the Petitioner

NIL

Documents marked for the Respondent

NIL

नई दिल्ली, 28 जून, 2018

का.आ. 1040.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार निदेशक, केन्द्रीय नमक और समुद्री रसायन अनुसंधान संस्थान, भावनगर (गुजरात) एवं उनके कर्मचारी के प्रबंधन के संबंध में नियोजकों और उनके कर्मचारियों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण एवं श्रम न्यायालय, भुवनेश्वर के पंचाट (संदर्भ संख्या 33/2016) को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 25.06.2018 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल-42025/03/2018-आईआर (डीयू)]

राजेंद्र जोशी, उप निदेशक

New Delhi, the 28th June, 2018

S.O. 1040.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award (I.D. No. 33/2016) of the Central Government Industrial Tribunal-cum-Labour Court, Bhubaneswar as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the Director, Central Salt and Marine Chemicals Research Institute, Bhavnagar (Gujarat) and their workmen, which was received by the Central Government on 25.06.2018.

[No. L-42025/03/2018-IR (DU)]

RAJENDRA JOSHI, Dy. Director

ANNEXURE

CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT, BHUBANESWAR

Present:

Shri B.C. Rath,
Presiding Officer, C.G.I.T.-cum-Labour
Court, Bhubaneswar

INDUSTRIAL DISPUTE CASE NO. 33/2016

Filed under section 2-A(2) of the I.D. Act

Date of Passing Order – 30th May, 2018

Between :

The Director,
Central Salt & Marine Chemicals
Research Institute, Gujubhai Badheka Marg,
Post Bhavanagar, Gujarat.- 364 002

...1st Party-Management

(And)

S. Chinneya @ S. Chinneta Rao,
S/o. Late S. Balabhadra Rao,
Bijipur, Boarding Street,
Po. Berhampur, Ps. B. Town,
Ganjam, Odisha – 760 001

...2nd Party-Petitioner

Appearances:

Shri T. Rambabu,
Section Officer.

... For the 1st Party-
Management

S. Chinneya & S. Chinneta Rao

.... For the Applicant-2nd Party

ORDER

This order is directed against the petition dated 31.05.2017 moved by the Management of Central Salt & Marine Chemicals Research, Bhavnagar wherein prayer has been made to dismiss the application of the applicant-workman preferred under section 2-A(2) of the Industrial Disputes Act on a contention that the Management being a registered research society under CSIR is not an “Industry” as defined under section 2(J) of the Industrial Disputes Act, 1947 (herein-after referred to as “The Act”). While opposing the petition the applicant-workman has submitted that the Management undertakes various project work and disseminates the research result to different sponsored agencies for monetary benefit and having fulfilled the triple tests as set-out by the Hon’ble Apex Court in the case of Bangalore Water Supply and Sewerage Board –versus- A. Rajappa the Management can be safely held as an “Industry”.

It is seen from the record that the applicant-workman has filed an application resorting to the provisions of Section 2-A(2) alleging that he was working as an Attendant-cum-Watchman in the Opp. Party-Management Centre at Berhampur from the year 1984. The centre at Berhampur was closed on October, 2002 without any prior notice and he was disengaged. The Management re-started its function again in Berhampur University campus from the year 2005. When he made a complaint before the Regional Labour Commissioner (Central) about his disengagement without compliance of the provisions of the I.D. Act, a conciliation proceeding was initiated. As per the settlement reached out in the said conciliation proceeding he joined in the field station at Berhampur with effect from 1.2.2007. According to him the Management refused employment to him with effect from March, 2015 without complying the provisions of the I.D. Act. The application is resisted by the Management on a pleading that the establishment is not an "Industry" and it is a research institute. The workman was never employed or engaged. Labourers were hired through the contractor and as such there was no scope of "employer or employee" relationship between the parties. The contractual appointment was for a specific period as the field station was functioning in the event of a particular project. The project having been closed the Management has no establishment at Berhampur. The project was for a specific period and the project having been closed there is no scope for the Management to employ the applicant-workman.

On the aforesaid pleadings of the parties the Management desires to decide the maintainability of the case as a preliminary issue. Hence the question arises for consideration at this stage is whether the Management of Central Salt & Marine Chemicals Research Institute, Bhavnagar is an "Industry" within the meaning of Section 2(j) of the I.D. Act.

Though the workman has pleaded that the establishment of the Management is an Industry nothing has been specifically pleaded in his application to show as to how the Management being a research institute and its project work at Berhampur is connected with any production, supply or distribution of goods or services. The mere fact that CSIR is carrying on in an organized and systematic manner and activity of research done by the organization by active participation between itself and its employees are not sufficient cause to bring it under the purview of "Industry" as defined under the I.D. Act. It is not the case of the applicant that activity of the Management involves businesses, trade or manufacture. There is no specific pleading in the application of the workman to show that the nature and character of the activity carried by the Management involves business, trade or manufacture. It is not pleaded that the Management is also involved with the researches which are commercial in nature. It is not producing or distributing services which are intended or meant for satisfying human wants or needs. There is no pleading to show that the knowledge acquired by the research institute is being marketed or it has commercial value. It has not pointed out as to how the knowledge acquired by the institute or the results of the research are useful to common people other than those engaged in such type of study. Having regard to the above facts a doubt can be entertained if the Management can be covered under the purview of "Industry" as defined under the Act. Hence, the application under section 2-A(2) filed by the applicant-workman does not seem to be maintainable under the I.D. Act and as such the same is dismissed in the event of the preliminary issue "whether the management of ICAR is an "industry" having goes against the applicant-workman.

Dictated & Corrected by me.

B. C. RATH, Presiding Officer

नई दिल्ली, 28 जून, 2018

का.आ. 1041.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड (नेफेड) नेफेड हाउस एवं उनके कर्मचारी के प्रबंधन के संबंध में नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण एवं श्रम न्यायालय सं. 2, दिल्ली के पंचाट (संदर्भ संख्या 19/2017) को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 17.05.2018 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल-42012/134/2016-आईआर (डीयू)]

राजेंद्र जोशी, उप निदेशक

New Delhi, the 28th June, 2018

S.O. 1041.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award (I.D. No. 19/2017) of the Central Government Industrial Tribunal-cum-Labour Court No. 2, Delhi as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the National Agricultural Co-operative Marketing Federation of India Ltd. (NAFED), NAFED House and their workmen, which was received by the Central Government on 17.05.2018.

[No. L-42012/134/2016-IR (DU)]

RAJENDRA JOSHI, Dy. Director

ANNEXURE**IN THE COURT OF SHRI AVTAR CHAND DOGRA, PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT NO.2, KARKARDOOMA COURT COMPLEX, DELHI****I.D.No. 19/2017**

Shri Sunil Rawat S/o Shri Dham Singh
R/o Flat No.C-422-A, Sector 19,
NOIDA, Distt. G.B. Nagar,
Uttar Pradesh – 201 301

...Workman

Versus

National Agricultural Co-operative Marketing
Federation of India Ltd. (NAFED), NAFED House

...Management...

AWARD

A reference was received from the appropriate Government vide letter No.L-42012/134/2016-IR(DU) dated 07.06.2017 under clause (d) of sub-section (1) and sub-section (2A) of Section 10 of the Act, for adjudication of a dispute, terms of which are as under:

‘Whether the workman Shri Sunil Rawat, S/o Shri Dham Singh is entitled for reinstatement on the post of peon with the Management of NAFED, New Delhi with all consequential benefits? If not, then what relief the workman is entitled to?’

2. Both parties were put to notice and 11th September, 2017 was fixed for filing of claim statement by the claimant. The claimant appeared before this Tribunal on 11.09.2017 and stated at the bar that he has joined the management as peon on 03.03.2017 as per office memorandum No.HO/AD/3/241/2016-17/10042 dated 28.02.2017 Exhibit C-1 and that his claim stands satisfied. His statement was recorded on 11.09.2017.

8. In view of the statement made by the claimant, no controversy survives between the parties. Office Memorandum Exhibit C-1 and the statement made by the claimant shall form integral part of the award. An award is, accordingly, passed. It be sent to the appropriate Government for publication, as required under Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947.

Dated : October 24, 2017

A. C. DOGRA, Presiding Officer

नई दिल्ली, 28 जून, 2018

का.आ. 1042.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार मैसर्स दिल्ली मेट्रो रेल निगम सीसी-02 परियोजना, रोहिणी, दिल्ली और अन्य एवं उनके कर्मचारी के प्रबंधन के संबंध में नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण एवं श्रम न्यायालय सं. 2, दिल्ली के पंचाट (संदर्भ संख्या 111/2015) को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 17.05.2018 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल-42025/03/2018-आईआर (डीयू)]

राजेंद्र जोशी, उप निदेशक

New Delhi, the 28th June, 2018

S.O. 1042.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award (I.D. No. 111/2015) of the Central Government Industrial Tribunal-cum-Labour Court No. 2, Delhi as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the M/s. Delhi Metro Rail Corporation CC-02 Project, Rohini, Delhi & Others and their workmen, which was received by the Central Government on 17.05.2018.

[No. L-42025/03/2018-IR (DU)]

RAJENDRA JOSHI, Dy. Director

ANNEXURE**IN THE COURT OF SHRI AVTAR CHAND DOGRA, PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT NO.2, KARKARDOOMA COURT COMPLEX, DELHI****I.D. No. 111/2015**

Shri Pramod Kumar S/o Shri Paras Nath

Through

Rashtriya Mazdoor Shang (Regd.)
157, Pratap Khand, Vishwakarma Nagar,
Shahdara, Delhi – 110 095

...Workman

Versus

1. M/s Delhi Metro Rail Corporation CC-02 Project,
Sector 18, Rohini,
Delhi – 110 042
2. M/s J Kumar Infraproject Ltd.,
Sewage Pumping Station,
Rohini Sector 19, Delhi 110 085
3. M/s J. Kumar Infraproject Ltd.
16-A, Andheri Industrial Estate, Veera Desai Road,
Andheri (West),
Mumbai – 400 053

...Managements

AWARD

Present dispute has been raised by Shri Pramod Kumar (in short the claimant) under the provisions of sub-section (2) of section 2-A of the Industrial Disputes Act, 1947 (in short the Act). A period of 45 days stood expired from the date of making his application before the Conciliation Officer. Sub-section (2) of section 2-A of the Act empowers him to file a dispute before this Tribunal, without being referred by the appropriate Government. His contention stands substantiated by the provisions of sub-section (2) of section 2-A of the Act. Claimant has been given a right by the Act to approach this Tribunal in case of discharge, dismissal, retrenchment or otherwise termination of her service, without a dispute being referred by the appropriate Government under sub-section (1) of section 10 of the Act. Since dispute was within the period of limitation, as enacted by sub section (3), and answered requirements of sub-section (2) of section 2-A of the Act, it was registered as an industrial dispute, even without being referred for adjudication by the appropriate Government, under section 10(1) (d) of the Act.

2. It has been averred in the statement of claim that the claimant was working with Delhi Metro Rail Corporation (in short the management) through M/s J Kumar Infraproject Ltd.(in short the contractor) since 02.11.2012 on the post of machine operator. His last drawn wages was Rs.13,000.00. The claimant worked continuously with the contractors upto 10.01.2014 and he gave no chance of complaint to them. The contractor failed to pay wages for the overtime work performed by the claimant. The claimant approached the contractors several times for payment of overtime wages as well as various other legal facilities, which annoyed the contractor and out of vengeance pressurized the claimant to submit his resignation letter. He was not allowed to perform his duties from 10.01.2014 without assigning any reason. His earned wages for December 2013 has not been paid by the contractor. No one months' notice or pay in lieu thereof was given to the claimant. No seniority list was ever prepared or displayed by the contractors. It is further averred in the statement of claim that fresh hands have been hired thereafter and juniors to the claimant have been retained in service. The contractor refused to pay the claimant his wages or even take him back on duty despite making several visits to the office of the contractor. Demand notice was served on the contractors on 28.02.2014 to which no reply was received from the contractors. Aggrieved by the action of the management, the claimant filed a case before the Conciliation Officer, but due to the adamant attitude of the management/contractor, conciliation ended in a failure. Finally the claimant was constrained to approach this Tribunal for justice. The claimant prays for reinstatement with full back wages.

3. Written statement was filed by Delhi Metro Rail Corporation taking preliminary objections of non-existence of relationship of employer and employee between them and the claimant, not specifically mentioning as to from which management he is claiming relief etc. The management has denied the other material averments contained in the statement of claim. Finally, it has been prayed that the claim may be rejected.

4. Written statement was filed by the contractors also, taking preliminary objection of suppressing of material information and not approaching the Tribunal with clean hands etc. It is averred that the claimant was a temporary employee and working on payroll as Hyrda Operator. The claimant was irresponsible and careless. On 31.12.2013, the claimant was caught red handed stealing diesel. He was warned of termination in case he repeats the mistake. The claimant left the job of his own as he had got better opportunity. The contractors have denied the material facts contained in the statement of claim. Finally, it has been prayed that the claim may be dismissed.

5. Rejoinder was filed by the claimant to the written statement filed by the managements, wherein the claimant has reiterated the stand taken in the claim statement and denied the material facts contained in the written statements.

6. Based on the pleadings of the parties, this Tribunal, vide order dated 09.02.2017 framed the following issues and the case was listed for evidence of the claimant:

- (i) Whether termination of the claimant is illegal and unjustified? If so, its effect.
- (ii) Whether this Tribunal has jurisdiction to decide the claim petition if monthly salary of the claimant was more than Rs.10,000.00 per month?
- (iii) Whether the job of the claimant/workman was of temporary nature or of permanent nature? If so, its effects.
- (iv) Whether the job of the claimant was terminated by management No.2 and 3 without giving him one month prior notice? If so, its effect?
- (v) Whether the claimant has received final settlement amount? If so, its effects.
- (vi) To what relief the workman is entitled to and from which date?

7. In the meanwhile, parties stated that they intended to take steps for settlement. Good sense prevailed and the dispute was settled between the parties amicably. Joint application on behalf of the claimant and managements containing terms of settlement has been filed, which is Ex.C-1. In view of the fact that the parties had settled their dispute amicably, there remains no occasion to adjudicate the issues referred above.

8. Claimant made a statement to the effect that he was willing to accept Rs.25,000.00 (rupees twenty five thousand only) from M/s J Kumar Infraprojects Ltd. towards full and final settlement of his claim. Now, the claimant does not have any surviving dispute with any of the managements and the matter has been disposed of amicably between the parties. Statement of the claimant Shri Vinod Kumar Yadav recorded. Joint application filed on behalf of the claimant and the managements for recording compromise marked Ex.C-1 shall form integral part of the award. An award is, accordingly, passed. It be sent to the appropriate Government for publication.

Dated : October 5, 2017

A. C. DOGRA, Presiding Officer

नई दिल्ली, 28 जून, 2018

का.आ. 1043.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार महानिदेशक, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, नई दिल्ली और अन्य एवं उनके कर्मचारी के प्रबंधन के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण एवं श्रम न्यायालय सं. 1, दिल्ली के पंचाट (संदर्भ संख्या 11/2016) को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 11.05.2018 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल-42025/03/2018-आईआर (डीयू)]

राजेंद्र जोशी, उप निदेशक

New Delhi, the 28th June, 2018

S.O. 1043.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award (I.D. No. 11/2016) of the Central Government Industrial Tribunal-cum-Labour Court No. 1, Delhi as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the Director General, Archaeological Survey of India, New Delhi & Others and their workmen, which was received by the Central Government on 11.05.2018.

[No. L-42025/03/2018-IR (DU)]

RAJENDRA JOSHI, Dy. Director

ANNEXURE**IN THE COURT OF SHRI AVTAR CHAND DOGRA : PRESIDING OFFICER CENTRAL
GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT No.1,
DWARKA COURTS COMPLEX : NEW DELHI****ID No. 11/2016**

Shri Jagdish Prasad S/o. Ram Dulare,
 Shri Parmeshwari S/o. Shakal Yadeav,
 Shri Ram Kumar Yadav S/o. Shri Pyare Lal
 Through its General Secretary,
 All India Central PWD (MRM) Karamchari Sanghathan (Regd.)
 House No.4823, Gali No.13, Balbir Nagar Extn.,
 Shahdara, Delhi 110032

...Workman

Versus

1. The Director General,
 Archaeological Survey of India,
 Janpath, New Delhi.
2. The Superintendent,
 Delhi Circle,
 Archaeological Survey of India,
 Puratata Bhawan,
 GPO Campus, Block-D,
 3rd Floor, INA,
 New Delhi 110023

...Management

AWARD

This is a claim filed directly by the Workmen/claimants Jagdish Prasad, Parmeshwari and Ram Kumar Yadav under Section 2(A) of the Industrial Disputes Act (hereinafter referred to as "the Act"), with the averments that the workmen were engaged as daily wage workers by the Management in its Delhi circle in the year 1991, 1992 and 1993 respectively for day to day running maintenance works of different sites of Delhi circle area. The workmen had filed a case vide OA No.100/1995 before the Central Administrative Tribunal for seeking grant of temporary status and regularization of their respective services and the said OA was allowed. The Management challenged the order before Hon'ble High Court of Delhi vide W.P. (C) No. 6898/2002. During pendency of aforesaid Writ, the services of the workmen/claimants were terminated without any written order. When this fact was brought to the notice of Hon'ble High Court, direction dated 23-4-2004 were issued for reinstatement of services of the workmen and consequently, the workmen/claimants were reinstated w.e.f. 8/9/2004. However, vide order dated 18/9/2007 Hon'ble High Court finally set aside the order of the Hon'ble Central Administrative Tribunal, against which the workmen moved Special Leave Appeal before the Hon'ble Supreme Court but to no success and the said Leave Appeal was also dismissed by the Hon'ble Supreme Court vide order dated 15/3/2010. Thereafter the Management terminated the services of the workmen w.e.f. 16/3/2010 in violation of the provisions of the Act. The workmen requested the Management for reinstatement but to no avail and thereafter they filed their case before Conciliation Officer and during pendency of the proceedings, the Management issued letters to the workmen on 21/1/2015 for joining the duties and as such the claimants/workers joined their duties and are continuously working under the Management since 6/2/2015 but they have not been paid wages in respect of their termination period w.e.f. 16/3/2010 to 5/2/2015. Hence, they have prayed for passing an Award for making payment of back wages from 16/3/2010 to 5/2/2015.

2. The claim petition has been resisted by the Management who filed written statement. It is stated that allegations of the workmen regarding their disengagement w.e.f.16/3/2010 are false and that services of the workmen on daily basis was never terminated by the Management. In case the services of the workmen on daily wages were terminated by the Management, they should file a contempt petition before Hon'ble High Court. Prayer has been made for dismissal of the claim petition.
- 3) The claimants/workmen filed rejoinder, thereby denying all the allegations made by the Management and reiterated their own case as set up in the claim petition.
- 4) On the pleadings of the parties, following issue was framed on 25/11/2016 :-
 - 1) Whether claimant is entitled for payment of back wages for the period 16/3/2010 to 5/2/2015.

5) The Claimants in support of their case examined Jagdish Prasad (claimant No.1) as W.W.1 who tendered his evidence by way of affidavit Ex.WW1/A alongwith documents Ex.WW1/1 to Ex.WW1/12 and Ram Kumar Yadav (claimant No.3) as WW 2 who also tendered his evidence by way of affidavit Ex.WW2/A and relied on the documents so filed by WW1.

6) On the other hand, the Management did not adduce any evidence despite opportunities granted and ultimately evidence of the Management was closed vide order dated 17/1/2018.

Issue No. 1 :-

7) Before giving findings on this issue regarding payment of back wages, it is necessary to mention here that claimant has filed this claim under Section 2-A of the Act, which reads as under :-

“2-A Dismissal, etc of an individual workman to be deemed to be an industrial dispute (1) Where any employer discharges, dismisses, retrenches or otherwise terminates the services of an individual workman, any dispute or difference between the workman and his employer connected with, or arising out of, such discharge, dismissal, retrenchment or termination shall be deemed to be an industrial dispute notwithstanding that no other workman nor any union of workmen is a party to the dispute.

(2).....

3) The application referred to in sub-section (2) shall be made to the Labour Court or Tribunal before the expiry of three years from the date of discharge, dismissal, retrenchment or otherwise termination of service as specified in sub-section (1).”

It is clear from the bare perusal of the aforesaid provisions that claim application under Section 2-A is legally maintainable when any employer has discharged, dismissed, retrenched or otherwise terminated the services of an individual workman. Sub-section (3) of Section 2-A of the Act provides that such application has to be made before the expiry of three years from the date of discharge, dismissal, retrenchment or otherwise termination of the service of the workman.

8) Since in the case in hand, the workmen/claimants have not sought any relief relating to discharge, dismissal, retrenchment or termination etc. and the present claim petition has been filed, seeking award for making payment of back wages from 16-3-2010 to 5-2-2015, as such the same is not legally maintainable under Section 2-A of the Act. Learned A/R for the claimants/workmen has fairly conceded the legal position and submitted that the claimants have got a right to file fresh petition and as such, the present petition may be disposed of with liberty to the claimants to seek the remedy before appropriate forum. In the peculiar facts and circumstances of the case, it is held that dismissal of the above petition would not legally debar the claimant from seeking appropriate remedy under the relevant provisions of law from the Court of competent jurisdiction, as no controversy involved in this case has been adjudicated on merits.

9) In view of the aforesaid discussion, the present petition under Section 2-A of the Act regarding relief of payment of back wages, is held to be not legally maintainable before this Tribunal. As such, the claim petition is hereby dismissed with liberty to the claimants to seek appropriate remedy under the relevant provisions of law before the Court of competent jurisdiction. Copy of award be sent for publication as required under the Act.

Award is passed accordingly.

Dated : 13.04.2018

AVTAR CHAND DOGRA, Presiding Officer

नई दिल्ली, 28 जून, 2018

का.आ. 1044.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार प्रभारी अधिकारी, सैन्य फार्म अंबाला कैंट, अंबाला (पंजाब) एवं उनके कर्मचारी के प्रबंधन के संबंध निर्यातकों और उनके कर्मचारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण एवं श्रम न्यायालय, जयपुर के पंचाट (संदर्भ संख्या सीआईटी 12/1997) को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 09.03.2018 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल-14012/01/1996-आईआर (डीयू)]

राजेंद्र जोशी, उप निदेशक

New Delhi, the 28th June, 2018

S.O. 1044.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award (I.D. No. 12/1997) of the Central Government Industrial Tribunal-cum-Labour Court, Jaipur as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the Officer-in-

Charge, Military Farm Ambala Cantt., Ambala (Punjab) and their workmen, which was received by the Central Government on 09.03.2018.

[No. L-14012/01/1996-IR (DU)]

RAJENDRA JOSHI, Dy. Director

अनुबंध

न्यायाधीश, केन्द्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण, जयपुर

केस नं० सी.आई.टी. 12/1997

रैफरेंस: केन्द्र सरकार, श्रम मंत्रालय, नई दिल्ली का आदेश क० एल.—14012/1/96—आई.आर.(डीयू) दि. 26.02.1997

श्रीमति मीरा हजिरजन पत्नी श्री लल्लूराम केयर/ऑफ जैनत गैरसरिया मौहल्ला, नीयर मस्जिद, फर बाजार, बीकानेर, मार्फत श्री कान सिंह राठौड़, 858, देवी नगर, श्याम नगर विस्तार पोस्ट आफिस के पीछे, न्यू सांगानेर रोड, सोडाला, जयपुर।

———— प्रार्थी

बनाम

प्रभारी अधिकारी, सैन्य फार्म अम्बाला कैंन्ट, अम्बाला (पंजाब)

————अप्रार्थी

पीठासीन अधिकारी : गिरीश कुमार शर्मा, आर.एच.जे.एस

उपस्थित

प्रार्थी की ओर से विद्वान प्रतिनिधि श्री कान सिंह राठौड़।

अप्रार्थी की ओर से कोई उपस्थित नहीं।

दिनांक : 31.10.2017

अ वा र्द

केन्द्र सरकार, श्रम मंत्रालय नई दिल्ली ने उपरोक्त आदेश के जरिये निम्न विवाद इस न्यायाधिकरण को अधिनिर्णय हेतु निर्दिष्ट किया है:

“Whether the management of Military Farm Depot, Bikaner which has been shifted to Ambala Cantt. Ambala in May 95 is Justified in terminating the services of Smt. Meera Harijan (Workman) Sweeper w.e.f. 1-1-1988 after employing her more than 240 days in a year at military farm depot., Bikaner without paying her notice pay in lieu of notices of one month and reterenchment compensat in violetion of section 25 F of Industrial Disput Act, 1947? if not, to what relief the workman is entitled and from date?”

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर उभय पक्षकारान को नोटिस जारी किए गए। प्रार्थी कर्मकार की ओर से दिनांक 06.01.2001 को स्टेटमेंट ऑफ क्लेम पेश कर अभिकथन किया गया कि प्रार्थीया विपक्षी संस्थान में दिनांक 01.11.1984 से अंशकालीन सफाईकर्म के पद पर कार्यरत थी। प्रार्थीया की नियुक्ति अंशकालीन सफाईकर्म के पद पर की गई थी लेकिन प्रार्थीया से विपक्षी संस्थान द्वारा पूरे 8 घंटे प्रतिदिन कार्य लिया जाता था। विपक्षी संस्थान द्वारा प्रार्थीया को दिनांक 01.01.1988 को मौखिक आदेश से हटा दिया गया। प्रार्थीया द्वारा सेवामुक्ति से पूर्व एक वर्ष में 240 दिवस से अधिक कार्य किया है। प्रार्थीया को हटाने से पूर्व कोई वरिष्ठता सूची जारी नहीं की गयी जबकि विपक्षी संस्थान में प्रार्थीया से जूनियर श्रमिक काम कर रहे थे। विपक्षी संस्थान द्वारा प्रार्थीया को हटाने से पूर्व कोई नोटिस, आरोप पत्र, एक माह का नोटिस वेतन, छंटनी मुआवजा नहीं दिया गया जो कि औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 25 एफ का उल्लंघन है। अन्त में प्रार्थी प्रतिनिधि ने प्रार्थीया कर्मकार के सेवामुक्ति आदेश को अनुचित व अवैध घोषित कर उसे पिछले पूर्ण वेतन लाभों के साथ सेवा में बहाल करने का निवेदन किया है।

विपक्षी संस्थान द्वारा स्टेटमेंट ऑफ क्लेम जवाब प्रस्तुत कर अभिकथन किया कि विपक्षी संस्थान द्वारा प्रार्थीया की नियुक्ति नहीं की गई थी बल्कि प्रार्थीया पूर्णतया आकस्मिक रूप से अंशकालीन तौर पर सफाई का कार्य एक—दो घण्टों के लिए करती थी तथा प्रार्थीया अपनी मर्जी से काम पर आती थी तथा उसने स्वेच्छा से ही कार्य पर आना बंद कर दिया गया। प्रार्थीया द्वारा कभी लगातार कार्य नहीं किया गया। प्रार्थीया द्वारा एक वर्ष में 240 दिवस कभी कार्य नहीं किया गया। विपक्षी संस्थान केन्द्र सरकार के अधीन है जो उद्योग की परिभाषा में नहीं आता है। जब विपक्षी संस्थान द्वारा प्रार्थीया की नियुक्ति नहीं की गई और न ही उसे सेवामुक्ति किया गया है तो औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 25 एफ के उल्लंघन का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। अन्त में विपक्षी प्रतिनिधि द्वारा प्रार्थीया का क्लेम प्रथम दृष्ट्या खारिज किए जाने की प्रार्थना की है।

प्रार्थी कर्मकार श्रीमति मीरा हरिजन की ओर से स्टेटमेंट ऑफ क्लेम के समर्थन में स्वयं का शपथ पत्र पेश हुआ है। विपक्षी की ओर से कोई उपस्थित नहीं होने से प्रार्थी कर्मकार से जिरह नहीं की गई है। विपक्षी संस्थान की ओर से कोई साक्ष्य पेश नहीं हुई है।

मैंने प्रार्थी प्रतिनिधि की बहस सुनी, पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया।

प्रार्थी प्रतिनिधि की बहस की है कि प्रार्थीया कर्मकार ने एक वर्ष 240 दिवस कार्य किया है। समझौता अधिकारी, श्रम विभाग के समक्ष प्रस्तुत प्रतिवेदन से भी प्रार्थीया का एक वर्ष में 240 दिवस कार्य करना सिद्ध होता है। विपक्षी संस्थान द्वारा औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 25 एफ का उल्लंघन किया गया है। अतः प्रार्थीया कर्मकार के सेवामुक्ति आदेश को अवैध घोषित कर समस्त लाभ परिलाभ दिलाते हुये सेवा में बहाल करने का निवेदन किया है। प्रार्थी प्रतिनिधि ने अपने तथ्यों के समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टांत पेश किये हैं —

1. 1983 लेब आई सी 1865, गम्मन इंडिया लि० बनाम निरंजन दास
2. 1994 III एल एल जे 689, गौरीशंकर विश्वकर्मा बनाम ईगजल स्प्रिंग इण्डस्ट्रीज प्रा० लि० व अन्य।
3. सिविल अपील संख्या 4445/2006 निर्णय दिनांक 03.10.2008 न्यू इण्डिया एश्योरेंस कंपनी लि० बनाम ए. शंकरलिंगम।
4. आर एल आर 1989 (1) 156 यशवंत सिंह यादव बनाम स्टेट ऑफ राज० व अन्य
5. 2012 लेब आई सी 404, कान सिंह बनाम आयुर्वेद अधिकारी व अन्य।
6. सिविल अपील संख्या 3701/2015 गौरीशंकर बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान।
7. सिविल अपील संख्या 4370/2015 राज कुमार दीक्षित बनाम मै० विजय कुमार गौरीशंकर।
8. 2003 डवल्यू एल सी (यूसी) 523 जनरल मैनेजर बनाम लेबर कोर्ट व अन्य।
9. 2001 लेब आई सी 2814 सपन कुमार पंडित बनाम यू०पी० स्टेट।
10. 2006 एस सी सी (एल एण्ड एस) 702 जी.एम. हरियाणा रोडवेज बनाम पवन कुमार।
11. 2014 लेब आई सी 4266 रघुवीर सिंह बनाम जनरल मैनेजर हरियाणा रोडवेज
12. 1999 (2) एस सी टी 669 अजायब सिंह बनाम श्रीहिंद कोपरेटिव मार्केटिंग कम प्रोसेसिंग।
13. 2007 ए आई आर एस सी डवल्यू 1712 मै० श्रीराम इण्डस्ट्रीज एन्टरप्राइजेज बनाम महक सिंह व अन्य।
14. 2006 लेब आई सी 56 राम किशन गुर्जर बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान।
15. ए आई आर 1986 एस सी 132 एच डी सिंह बनाम आई बी आई।
16. सिविल अपील संख्या 1374/2008 निर्णय दिनांक 17.7.12 यूनियन ऑफ इण्डिया बनाम इब्राहिम उड्डिन व अन्य।
17. 2012 लेब आई सी 2520 राज० एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बनाम लक्ष्मणदान व अन्य।
18. 1963 (6) एस सी 431 हरिनगर केन फार्म बनाम स्टेट ऑफ बिहार।
19. 1978 एल एल जे (एस सी) 349 बंगलोर वाटर सप्लाई एण्ड सेवरेज बोर्ड बनाम ए राजाप्पा व अन्य।

अब न्यायाधिकरण के समक्ष अवधारणीय बिन्दु यह है कि क्या प्रार्थीया कर्मकार ने एक वर्ष में 240 दिवस या अधिक दिवस कार्य किया? इस संबंध में प्रार्थीया ने अपनी साक्ष्य शपथ पत्र पर प्रस्तुत की है जिसमें विपक्षी सैन्यफार्म में दिनांक 1.11.1984 से दैनिक वेतन भोगी के रूप में सफाई का कार्य करना आया है तथा दिनांक 1.1.988 को मौखिक आदेश से सेवामुक्ति किया जाना आया है तथा प्रार्थीया ने एक वर्ष में 240 दिवस से अधिक कार्य विपक्षी सैन्य फार्म जो कि डेयरी फार्म होना प्रार्थीया की साक्ष्य से प्रकट है तथा विपक्षी की ओर समझौता अधिकारी के यहां जवाब प्रदर्श डब्ल्यू 1 पेश किया गया जिसमें दिनांक 1.11.1984 से दिनांक 31.12.1987 तक कार्य किया जाना स्वीकारा है तथा प्रार्थीया के विद्वान प्रतिनिधि की ओर से प्रस्तुत न्यायिक विनिश्चयों का सम्मानपूर्वक परिशीलन से न्यायाधिकरण का विनम्र मत यह है कि जहां तक विपक्षी ने अपने जवाब में यह अभिकथन किया है कि प्रार्थीया पार्टटाईम वर्कर थी इस संबंध में औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 की धारा 2 (5) के प्रावधान में व उपरोक्त न्यायिक विनिश्चयों में प्रतिपादित सिद्धांत की रोशनी में प्रार्थी का कर्मकार की तारीफ आती है क्योंकि प्रार्थीया ने अपनी साक्ष्य में 8 घण्टे से अधिक कार्य रोजाना करना आया है जिसका विपक्षी की ओर से कोई खण्डन भी नहीं है। द्वितीय अंशकालीन कार्य करने वाले भी कर्मकार की तारीफ में आते हैं तथा प्रार्थीया के द्वारा दिनांक 1.11.1984 से 31.12.1987 तक तो स्वीपर का कार्य करना प्रदर्श डब्ल्यू 1 जो कि समझौता अधिकारी के यहां विपक्षी की ओर से जवाब पेश किया गया है उससे स्पष्ट है तथा जब 240 दिवस से अधिक कार्य किया जाना प्रार्थीया की साक्ष्य व दस्तावेज प्रदर्श डब्ल्यू-1 से स्पष्ट है तो विपक्षी के द्वारा प्रार्थीया को सेवामुक्ति दिनांक 1.1.1988 को किया तो कोई एक माह का वेतन नोटिस या क्षतिपूर्ति राशि दी गई हो ऐसा विपक्षी के जवाब से प्रकट नहीं है। अतः औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 की धारा 25 एफ का अतिलंघन किया जाना स्पष्ट है। अतः प्रार्थीया का सेवामुक्ति आदेश दिनांक 1.1.1988 विधिसम्मत नहीं है तथा अब न्यायाधिकरण को यह देखना है कि प्रार्थीया किस अनुतोष की हकदार है। चूंकि अभिलेख से स्पष्ट है कि प्रार्थीया की नियुक्ति विपक्षी स्थापन में किसी नियमित प्रक्रिया से नहीं हुई है तथा स्वीपर का पद नियमित कैडर का है या नहीं। ऐसी प्रार्थी की कोई साक्ष्य से स्थापित नहीं है इसलिए पुनर्स्थापन के बजाय प्रार्थीया की सेवाअवधि एवं कार्य की प्रकृति को देखते हुए एक लाख रुपये बतौर प्रतिकर विपक्षी से दिलाया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के फलस्वरूप इस रेफरेंस का उत्तर उपरोक्तानुसार देते हुए निम्न अधिनिर्णय पारित किया जाना समीचीन प्रतीत होता है —

अधिनिर्णय

अतः “विपक्षी सैन्य फार्म अम्बाला कैंन्ट, अम्बाला (पंजाब) द्वारा औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 25 एफ का उल्लंघन करना पाया जाता है तथा प्रार्थीया कर्मकार श्रीमति मीरा हरिजन को दिनांक 1.1.1988 से सेवा पर्यवसान किया जाना विधिसम्मत एवं न्यायोचित नहीं है तथा प्रार्थीया कर्मकार विपक्षी स्थापन से बतौर प्रतिकर के एक लाख रुपये पाने की मुश्तहक है जो विपक्षी स्थापन अधिनिर्णय की तिथि से 6 माह में प्रार्थीया कर्मकार श्रीमति मीरा हरिजन को संदाय करें अन्यथा प्रार्थी श्रमिक उक्त अवार्ड की तिथि से 6 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज पाने का हकदार रहेगा। मामले के तथ्य एवं परिस्थिति में पक्षकारान् खर्चा अपना अपना स्वयं वहन करेंगे।”

गिरीश कुमार शर्मा, न्यायाधीष

नई दिल्ली, 2 जुलाई, 2018

का.आ. 1045.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार मैसर्स सेन्ट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक्स इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नोलॉजी एवं अन्य के प्रबंधन के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण एवं श्रम न्यायालय-1, चंडीगढ़ के पंचाट (संदर्भ संख्या 38/2015) को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 28.06.2018 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल-30012/4/2016-आईआर (एम)]

डी. के. हिमांशु, अवर सचिव

New Delhi, the 2nd July, 2018

S.O. 1045.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award (Ref. No. 38/2015) of the Central Government Industrial Tribunal/Labour Court-1, Chandigarh now as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of M/s. Central Institute of Plastics Engineering & Technology and other and their workman, which was received by the Central Government on 28.06.2018.

[No. L-30012/4/2016-IR (M)]

D. K. HIMANSHU, Under Secy.

ANNEXURE

BEFORE PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVT. INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT-I, CHANDIGARH

Case No. ID No. 38 of 2015

Sh. Dharmender Sahani, S/o Sh. Swami Nath, Vill-Singhpura,
PO-Behouli, Teh. & Distt. Panipat (Haryana)-132101

...Workman

Versus

1. M/s Central Institute of Plastics Engineering & Technology,
DCRUST Campus, 50th Mile Stone, NH-1, Murthal,
Distt. Sonapat (Haryana)-131027.
2. M/s Super Detective Security Services, Asandh Road,
Panipat (Haryana)-132103

...Respondents

Award Dated : 26.04.2018

A reference was received from the Government of India vide reference No. L-30012/4/2016-IR(M) Order Dated 14.03.2016 under Section 10 sub-Section 2(A) and sub-section 1, clause (d) of the Industrial Disputes Act, 1947(in short the Act) for adjudication of an industrial dispute terms of which are as under:-

“Whether the action of the management M/s Central Institute of Plastics Engineering & Technology, Sonipat and M/s Super Detective Security Services Panipat in not accepting the demands regarding payment of final demands of the workmen Sh. Dharmender Sahani S/o Sh. Swami Nath, is legal and justified? If not, what relief the workman is entitled to and from which date?”

It is clear from the statement of claim that workman was appointed with respondent no.1 i.e. M/s Central Institute of Plastics Engineering & Technology, DCRUST Campus, 50th Mile Stone, NH-1, Murthal, Distt. Sonapat(Haryana),

which is a Central Government undertaking by following the due procedure under the Law. The workman has claimed arrears of the facilities like wages at double rates for working on Saturday and Sunday or any other holiday. Uniform and Safety Shoes, Dust Allowance, Annual Bonus, Annual Leave with wages after completion of 240 days.

The above facilities and allowances were not paid to the workman despite demand notice as such, claim was filed. No written statement was filed on behalf of the management. This Court tried conciliation between the parties and parties finally amicably settled the matter vide a settlement Exb.C-1. Statement of the workman has been recorded, who is accepted the settlement Exb.C-1. The workman does not want to pursue the claim petition.

Resultantly, the claim filed by the workman is settled in terms of Exb.C-1, which shall form integral part of this award.

Let copy of this award be sent to the Central Government for publication as required under Section 17 of the Act.

A. C. DOGRA, Presiding Officer-cum-Link Officer

नई दिल्ली, 2 जुलाई, 2018

का.आ. 1046.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार मैसर्स सेन्ट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक्स इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नोलॉजी एवं अन्य के प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण एवं श्रम न्यायालय-1, चंडीगढ़ के पंचाट (संदर्भ संख्या 39/2015) को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 28.06.2018 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल-30012/5/2016-आईआर (एम)]

डी. के. हिमांशु, अवर सचिव

New Delhi, the 2nd July, 2018

S.O. 1046.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award (Ref. No. 39/2015) of the Central Government Industrial Tribunal/Labour Court-1, Chandigarh now as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of M/s. Central Institute of Plastics Engineering & Technology and other and their workman, which was received by the Central Government on 28.06.2018.

[No. L-30012/5/2016-IR (M)]

D. K. HIMANSHU, Under Secy.

ANNEXURE

BEFORE PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVT. INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT-I, CHANDIGARH

Case No. ID No. 39 of 2015

Sh. Bisram Paswan, S/o Sh. Kapil Dev, Village & PO-Moonak,
Teh. Bhalla, Distt. Karnal (Haryana)-132040

...Workman

Versus

1. M/s Central Institute of Plastics Engineering & Technology,
DCRUST Campus, 50th Mile Stone, NH-1, Murthal,
Distt. Sonapat (Haryana)-131027.

2. M/s Super Detective Security Services, Asandh Road,
Panipat (Haryana)-132103

...Respondents

Award Dated : 26.04.2018

A reference was received from the Government of India vide reference No.L30012/5/2016-IR(M), Order Dated 14.03.2016 under Section 10 sub-Section 2(A) and sub-section 1, clause (d) of the Industrial Disputes Act, 1947(in short the Act) for adjudication of an industrial dispute terms of which are as under:-

“Whether the action of the management M/s Central Institute of Plastics Engineering & Technology, Sonipat and M/s Super Detective Security Services Panipat in not accepting the demands regarding payment of final demands of the workmen Sh. Vishram Paswan S/o Sh. Kapil Dev, is legal and justified? If not, what relief the workman is entitled to and from which date?”

It is clear from the statement of claim that workman was appointed with respondent no.1 i.e. M/s Central Institute of Plastics Engineering & Technology, DCRUST Campus, 50th Mile Stone, NH-1, Murthal, Distt. Sonapat(Haryana),

which is a Central Government undertaking by following the due procedure under the Law. The workman has claimed arrears of the facilities like wages at double rates for working on Saturday and Sunday or any other holiday. Uniform and Safety Shoes, Dust Allowance, Annual Bonus, Annual Leave with wages after completion of 240 days.

The above facilities and allowances were not paid to the workman despite demand notice as such, claim was filed. No written statement was filed on behalf of the management. This Court tried conciliation between the parties and parties finally amicably settled the matter vide a settlement Exb.C-1. Statement of the workman has been recorded, who is accepted the settlement Exb.C-1. The workman does not want to pursue the claim petition.

Resultantly, the claim filed by the workman is settled in terms of Exb.C-1, which shall form integral part of this award.

Let copy of this award be sent to the Central Government for publication as required under Section 17 of the Act.

A. C. DOGRA, Presiding Officer-cum-Link Officer

नई दिल्ली, 2 जुलाई, 2018

का.आ. 1047.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार मैसर्स सेन्ट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक्स इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नोलॉजी एवं अन्य के प्रबंधन के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण एवं श्रम न्यायालय-1, चंडीगढ़ के पंचाट (संदर्भ संख्या 40/2015) को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 28.06.2018 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल-30012/6/2016-आईआर (एम)]

डी. के. हिमांशु, अवर सचिव

New Delhi, the 2nd July, 2018

S.O. 1047.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award (Ref. No. 40/2015) of the Central Government Industrial Tribunal/Labour Court-1, Chandigarh now as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of M/s. Central Institute of Plastics Engineering & Technology and other and their workman, which was received by the Central Government on 28.06.2018.

[No. L-30012/6/2016-IR (M)]

D. K. HIMANSHU, Under Secy.

ANNEXURE

BEFORE PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVT. INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT-I, CHANDIGARH

Case No. ID No. 40 of 2015

Sh. Sanjay Kumar, S/o Sh. Balbir Singh, Village & PO-Dahar,
Teh. & Distt. Panipat (Haryana)-132145

...Workman

Versus

1. M/s Central Institute of Plastics Engineering & Technology,
DCRUST Campus, 50th Mile Stone, NH-1, Murthal,
Distt. Sonapat (Haryana)-131027.
2. M/s Super Detective Security Services, Asandh Road,
Panipat (Haryana)-132103

...Respondents

Award Dated : 26.04.2018

A reference was received from the Government of India vide reference No.L-30012/6/2016-IR(M) Order Dated 14.03.2016 under Section 10 sub-Section 2(A) and sub-section 1, clause (d) of the Industrial Disputes Act, 1947(in short the Act) for adjudication of an industrial dispute terms of which are as under:-

“Whether the action of the management M/s Central Institute of Plastics Engineering & Technology, Sonipat and M/s Super Detective Security Services Panipat in not accepting the demands regarding payment of final demands of the workmen Sh. Sanjay Kumar S/o Sh. Balbir Singh, is legal and justified? If not, what relief the workman is entitled to and from which date?”

It is clear from the statement of claim that workman was appointed with respondent no.1 i.e. M/s Central Institute of Plastics Engineering & Technology, DCRUST Campus, 50th Mile Stone, NH-1, Murthal, Distt. Sonapat(Haryana),

which is a Central Government undertaking by following the due procedure under the Law. The workman has claimed arrears of the facilities like wages at double rates for working on Saturday and Sunday or any other holiday. Uniform and Safety Shoes, Dust Allowance, Annual Bonus, Annual Leave with wages after completion of 240 days.

The above facilities and allowances were not paid to the workman despite demand notice as such, claim was filed. No written statement was filed on behalf of the management. This Court tried conciliation between the parties and parties finally amicably settled the matter vide a settlement Exb.C-1. Statement of the workman has been recorded, who is accepted the settlement Exb.C-1. The workman does not want to pursue the claim petition.

Resultantly, the claim filed by the workman is settled in terms of Exb.C-1, which shall form integral part of this award.

Let copy of this award be sent to the Central Government for publication as required under Section 17 of the Act.

A. C. DOGRA, Presiding Officer-cum-Link Officer

नई दिल्ली, 2 जुलाई, 2018

का.आ. 1048.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार मैसर्स सेन्ट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक्स इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नोलॉजी एवं अन्य के प्रबंधन के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण एवं श्रम न्यायालय-1, चंडीगढ़ के पंचाट (संदर्भ संख्या 41/2015) को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 28.06.2018 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल-30012/7/2016-आईआर (एम)]

डी. के. हिमांशु, अवर सचिव

New Delhi, the 2nd July, 2018

S.O. 1048.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award (Ref. No. 41/2015) of the Central Government Industrial Tribunal/Labour Court-1, Chandigarh now as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of M/s. Central Institute of Plastics Engineering & Technology and other and their workman, which was received by the Central Government on 28.06.2018.

[No. L-30012/7/2016-IR (M)]

D. K. HIMANSHU, Under Secy.

ANNEXURE

BEFORE PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVT. INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT-I, CHANDIGARH

Case No. ID No. 41 of 2015

Sh. Satbir Singh, S/o Sh. Karan Singh, Village & PO-Bhinjol,
Teh. & Distt. Panipat (Haryana)-132103

...Workman

Versus

1. M/s Central Institute of Plastics Engineering & Technology,
DCRUST Campus, 50th Mile Stone, NH-1, Murthal,
Distt. Sonapat (Haryana)-131027.
2. M/s Super Detective Security Services, Asandh Road,
Panipat (Haryana)-132103

...Respondents

AWARD

Dated : 26.04.2018

A reference was received from the Government of India vide reference No.L-30012/7/2016-IR(M) Order Dated 14.03.2016 under Section 10 sub-Section 2(A) and sub-section 1, clause (d) of the Industrial Disputes Act, 1947 (in short the Act) for adjudication of an industrial dispute terms of which are as under:-

“Whether the action of the management M/s Central Institute of Plastics Engineering & Technology, Sonipat and M/s Super Detective Security Services Panipat in not accepting the demands regarding payment of final demands of the workmen Sh. Satbir Singh S/o Sh. Karan Singh, is legal and justified? If not, what relief the workman is entitled to and from which date?”

It is clear from the statement of claim that workman was appointed with respondent no.1 i.e. M/s Central Institute of Plastics Engineering & Technology, DCRUST Campus, 50th Mile Stone, NH-1, Murthal, Distt. Sonapat(Haryana),

which is a Central Government undertaking by following the due procedure under the Law. The workman has claimed arrears of the facilities like wages at double rates for working on Saturday and Sunday or any other holiday. Uniform and Safety Shoes, Dust Allowance, Annual Bonus, Annual Leave with wages after completion of 240 days.

The above facilities and allowances were not paid to the workman despite demand notice as such, claim was filed. No written statement was filed on behalf of the management. This Court tried conciliation between the parties and parties finally amicably settled the matter vide a settlement Exb.C-1. Statement of the workman has been recorded, who is accepted the settlement Exb.C-1. The workman does not want to pursue the claim petition.

Resultantly, the claim filed by the workman is settled in terms of Exb.C-1, which shall form integral part of this award.

Let copy of this award be sent to the Central Government for publication as required under Section 17 of the Act.

A. C. DOGRA, Presiding Officer-cum-Link Officer

नई दिल्ली, 2 जुलाई, 2018

का.आ. 1049.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार मैसर्स सेन्ट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक्स इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नोलॉजी एवं अन्य के प्रबंधन के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण एवं श्रम न्यायालय-1, चंडीगढ़ के पंचाट (संदर्भ संख्या 42/2015) को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 28.06.2018 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल-30012/8/2016-आईआर (एम)]

डी. के. हिमांशु, अवर सचिव

New Delhi, the 2nd July, 2018

S.O. 1049.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award (Ref. No. 42/2015) of the Central Government Industrial Tribunal/Labour Court-1, Chandigarh now as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of M/s. Central Institute of Plastics Engineering & Technology and other and their workman, which was received by the Central Government on 28.06.2018.

[No. L-30012/8/2016-IR (M)]

D. K. HIMANSHU, Under Secy.

ANNEXURE

BEFORE PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVT. INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT-I, CHANDIGARH

Case No. ID No. 42 of 2015

Sh. Prince Chokkar, S/o Sh. Maman Singh, Village & PO-Paina Khurd,
Tehsil Bhapoli & Distt. Panipat (Haryana)-132104

...Workman

Versus

3. M/s Central Institute of Plastics Engineering & Technology,
DCRUST Campus, 50th Mile Stone, NH-1, Murthal,
Distt. Sonapat (Haryana)-131027.

4. M/s Super Detective Security Services, Asandh Road,
Panipat (Haryana)-132103

...Respondents

Award Dated : 26.04.2018

A reference was received from the Government of India vide reference No.L-30012/8/2016-IR(M) Order Dated 14.03.2016 under Section 10 sub-Section 2(A) and sub-section 1, clause (d) of the Industrial Disputes Act, 1947(in short the Act) for adjudication of an industrial dispute terms of which are as under:-

"Whether the action of the management M/s Central Institute of Plastics Engineering & Technology, Sonipat and M/s Super Detective Security Services Panipat in not accepting the demands regarding payment of final demands of the workmen Sh. Prince Chhokar S/o Sh. Maman Singh, is legal and justified? If not, what relief the workman is entitled to and from which date?"

It is clear from the statement of claim that workman was appointed with respondent no.1 i.e. M/s Central Institute of Plastics Engineering & Technology, DCRUST Campus, 50th Mile Stone, NH-1, Murthal, Distt. Sonapat(Haryana),

which is a Central Government undertaking by following the due procedure under the Law. The workman has claimed arrears of the facilities like wages at double rates for working on Saturday and Sunday or any other holiday. Uniform and Safety Shoes, Dust Allowance, Annual Bonus, Annual Leave with wages after completion of 240 days.

The above facilities and allowances were not paid to the workman despite demand notice as such, claim was filed. No written statement was filed on behalf of the management. This Court tried conciliation between the parties and parties finally amicably settled the matter vide a settlement Exb.C-1. Statement of the workman has been recorded, who is accepted the settlement Exb.C-1. The workman does not want to pursue the claim petition.

Resultantly, the claim filed by the workman is settled in terms of Exb.C-1, which shall form integral part of this award.

Let copy of this award be sent to the Central Government for publication as required under Section 17 of the Act.

A. C. DOGRA, Presiding Officer-cum-Link Officer

नई दिल्ली, 2 जुलाई, 2018

का.आ. 1050.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार मैसर्स सेन्ट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक्स इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नोलॉजी एवं अन्य के प्रबंधन के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण एवं श्रम न्यायालय-1, चंडीगढ़ के पंचाट (संदर्भ संख्या 45/2015) को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 28.06.2018 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल-30012/11/2016-आईआर (एम)]

डी. के. हिमांशु, अवर सचिव

New Delhi, the 2nd July, 2018

S.O. 1050.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award (Ref. No. 45/2015) of the Central Government Industrial Tribunal/Labour Court-1, Chandigarh now as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of M/s. Central Institute of Plastics Engineering & Technology and other and their workman, which was received by the Central Government on 28.06.2018.

[No. L-30012/11/2016-IR (M)]

D. K. HIMANSHU, Under Secy.

ANNEXURE

BEFORE PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVT. INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT-I, CHANDIGARH

Case No. ID No. 45 of 2015

Sh. Vikas, S/o Sh. Rajbir Singh, Village & PO-Naultha,
Tehsil Ishrana, Distt. Panipat (Haryana)-132040

...Workman

Versus

1. M/s Central Institute of Plastics Engineering & Technology,
DCRUST Campus, 50th Mile Stone, NH-1, Murthal,
Distt. Sonapat (Haryana)-131027.

2. M/s Super Detective Security Services, Asandh Road,
Panipat (Haryana)-132103

...Respondents

Award Dated : 26.04.2018

A reference was received from the Government of India vide reference No.L-30012/11/2016-IR(M) Order Dated 14.03.2016 under Section 10 sub-Section 2(A) and sub-section 1, clause (d) of the Industrial Disputes Act, 1947(in short the Act) for adjudication of an industrial dispute terms of which are as under:-

"Whether the action of the management M/s Central Institute of Plastics Engineering & Technology, Sonipat and M/s Super Detective Security Services Panipat in not accepting the demands regarding payment of final demands of the workmen Sh. Vikas S/o Sh. Rajbir Singh, is legal and justified? If not, what relief the workman is entitled to and from which date?"

It is clear from the statement of claim that workman was appointed with respondent no.1 i.e. M/s Central Institute of Plastics Engineering & Technology, DCRUST Campus, 50th Mile Stone, NH-1, Murthal, Distt. Sonapat(Haryana),

which is a Central Government undertaking by following the due procedure under the Law. The workman has claimed arrears of the facilities like wages at double rates for working on Saturday and Sunday or any other holiday. Uniform and Safety Shoes, Dust Allowance, Annual Bonus, Annual Leave with wages after completion of 240 days.

The above facilities and allowances were not paid to the workman despite demand notice as such, claim was filed. No written statement was filed on behalf of the management. This Court tried conciliation between the parties and parties finally amicably settled the matter vide a settlement Exb.C-1. Statement of the workman has been recorded, who is accepted the settlement Exb.C-1. The workman does not want to pursue the claim petition.

Resultantly, the claim filed by the workman is settled in terms of Exb.C-1, which shall form integral part of this award.

Let copy of this award be sent to the Central Government for publication as required under Section 17 of the Act.

A. C. DOGRA, Presiding Officer-cum-Link Officer

नई दिल्ली, 2 जुलाई, 2018

का.आ. 1051.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार मैसर्स सेन्ट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक्स इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नोलॉजी एवं अन्य के प्रबंधन के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण एवं श्रम न्यायालय-1, चंडीगढ़ के पंचाट (संदर्भ संख्या 46/2015) को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 28.06.2018 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल-30012/12/2016-आईआर (एम)]

डी. के. हिमांशु, अवर सचिव

New Delhi, the 2nd July, 2018

S.O. 1051.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award (Ref. No. 46/2015) of the Central Government Industrial Tribunal/Labour Court-1, Chandigarh now as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of M/s. Central Institute of Plastics Engineering & Technology and other and their workman, which was received by the Central Government on 28.06.2018.

[No. L-30012/12/2016-IR (M)]

D. K. HIMANSHU, Under Secy.

ANNEXURE

BEFORE PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVT. INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT-I, CHANDIGARH

Case No. ID No. 46 of 2015

Sh. Parveen Kumar, S/o Sh. Suresh Kumar, Village & PO-Barsat,
Tehsil Gharaunda, Distt. Karnal (Haryana)-132027

...Workman

Versus

1. M/s Central Institute of Plastics Engineering & Technology,
DCRUST Campus, 50th Mile Stone, NH-1, Murthal,
Distt. Sonapat (Haryana)-131027.

2. M/s Super Detective Security Services, Asandh Road,
Panipat (Haryana)-132103

...Respondents

Award Dated : 26.04.2018

A reference was received from the Government of India vide reference No.L-30012/12/2016-IR(M) Order Dated 14.03.2016 under Section 10 sub-Section 2(A) and sub-section 1, clause (d) of the Industrial Disputes Act, 1947(in short the Act) for adjudication of an industrial dispute terms of which are as under:-

"Whether the action of the management M/s Central Institute of Plastics Engineering & Technology, Sonipat and M/s Super Detective Security Services Panipat in not accepting the demands regarding payment of final demands of the workmen Sh. Parveen Kumar S/o Sh. Suresh Kumar, is legal and justified? If not, what relief the workman is entitled to and from which date?"

It is clear from the statement of claim that workman was appointed with respondent no.1 i.e. M/s Central Institute of Plastics Engineering & Technology, DCRUST Campus, 50th Mile Stone, NH-1, Murthal, Distt. Sonapat(Haryana),

which is a Central Government undertaking by following the due procedure under the Law. The workman has claimed arrears of the facilities like wages at double rates for working on Saturday and Sunday or any other holiday. Uniform and Safety Shoes, Dust Allowance, Annual Bonus, Annual Leave with wages after completion of 240 days.

The above facilities and allowances were not paid to the workman despite demand notice as such, claim was filed. No written statement was filed on behalf of the management. This Court tried conciliation between the parties and parties finally amicably settled the matter vide a settlement Exb.C-1. Statement of the workman has been recorded, who is accepted the settlement Exb.C-1. The workman does not want to pursue the claim petition.

Resultantly, the claim filed by the workman is settled in terms of Exb.C-1, which shall form integral part of this award.

Let copy of this award be sent to the Central Government for publication as required under Section 17 of the Act.

A. C. DOGRA, Presiding Officer-cum-Link Officer

नई दिल्ली, 2 जुलाई, 2018

का.आ. 1052.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार मैसर्स सेन्ट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक्स इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नोलॉजी एवं अन्य के प्रबंधन के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण एवं श्रम न्यायालय-1, चंडीगढ़ के पंचाट (संदर्भ संख्या 48/2015) को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 28.06.2018 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल-30012/14/2016-आईआर (एम)]

डी. के. हिमांशु, अवर सचिव

New Delhi, the 2nd July, 2018

S.O. 1052.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award (Ref. No. 48/2015) of the Central Government Industrial Tribunal/Labour Court-1, Chandigarh now as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of M/s. Central Institute of Plastics Engineering & Technology and other and their workman, which was received by the Central Government on 28.06.2018.

[No. L-30012/14/2016-IR (M)]

D. K. HIMANSHU, Under Secy.

ANNEXURE

BEFORE PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVT. INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT-I, CHANDIGARH

Case No. ID No. 48 of 2015

Sh. Vivek Kumar, S/o Sh. Satesheari, Village & PO-Sithana,
Tehsil & Distt. Panipat (Haryana)-132103

...Workman

Versus

1. M/s Central Institute of Plastics Engineering & Technology,
DCRUST Campus, 50th Mile Stone, NH-1, Murthal,
Distt. Sonapat (Haryana)-131027.

2. M/s Super Detective Security Services, Asandh Road,
Panipat (Haryana)-132103

...Respondents

Award Dated : 26.04.2018

A reference was received from the Government of India vide reference No.L-30012/14/2016-R(M)Order Dated 14.03.2016 under Section 10 sub-Section 2(A) and sub-section 1, clause (d) of the Industrial Disputes Act, 1947(in short the Act) for adjudication of an industrial dispute terms of which are as under:-

"Whether the action of the management M/s Central Institute of Plastics Engineering & Technology, Sonipat and M/s Super Detective Security Services Panipat in not accepting the demands regarding payment of final demands of the workmen Sh. Vivek Kumar S/o Sh. Ateshwari Parsad, is legal and justified? If not, what relief the workman is entitled to and from which date?"

It is clear from the statement of claim that workman was appointed with respondent no.1 i.e. M/s Central Institute of Plastics Engineering & Technology, DCRUST Campus, 50th Mile Stone, NH-1, Murthal, Distt. Sonapat(Haryana),

which is a Central Government undertaking by following the due procedure under the Law. The workman has claimed arrears of the facilities like wages at double rates for working on Saturday and Sunday or any other holiday. Uniform and Safety Shoes, Dust Allowance, Annual Bonus, Annual Leave with wages after completion of 240 days.

The above facilities and allowances were not paid to the workman despite demand notice as such, claim was filed. No written statement was filed on behalf of the management. This Court tried conciliation between the parties and parties finally amicably settled the matter vide a settlement Exb.C-1. Statement of the workman has been recorded, who is accepted the settlement Exb.C-1. The workman does not want to pursue the claim petition.

Resultantly, the claim filed by the workman is settled in terms of Exb.C-1, which shall form integral part of this award.

Let copy of this award be sent to the Central Government for publication as required under Section 17 of the Act.

A. C. DOGRA, Presiding Officer-cum-Link Officer

नई दिल्ली, 2 जुलाई, 2018

का.आ. 1053.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार मैसर्स सेन्ट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक्स इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नोलॉजी एवं अन्य के प्रबंधन के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण एवं श्रम न्यायालय-1, चंडीगढ़ के पंचाट (संदर्भ संख्या 49/2015) को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 28.06.2018 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल-30012/15/2016-आईआर (एम)]

डी. के. हिमांशु, अवर सचिव

New Delhi, the 2nd July, 2018

S.O. 1053.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award (Ref. No. 49/2015) of the Central Government Industrial Tribunal/Labour Court-1, Chandigarh now as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of M/s. Central Institute of Plastics Engineering & Technology and other and their workman, which was received by the Central Government on 28.06.2018.

[No. L-30012/15/2016-IR (M)]

D. K. HIMANSHU, Under Secy.

ANNEXURE

BEFORE PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVT. INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT-I, CHANDIGARH

Case No. ID No. 49 of 2015

Sh. Rakesh, S/o Sh. Pala Ram, Village & PO-Kalro,
Tehsil Gharaunda, Distt. Karnal (Haryana)-132114

...Workman

Versus

1. M/s Central Institute of Plastics Engineering & Technology,
DCRUST Campus, 50th Mile Stone, NH-1, Murthal,
Distt. Sonapat (Haryana)-131027.

2. M/s Super Detective Security Services, Asandh Road,
Panipat (Haryana)-132103

...Respondents

Award Dated : 26.04.2018

A reference was received from the Government of India vide reference No.L-30012/15/2016-IR(M) Order Dated 14.03.2016 under Section 10 sub-Section 2(A) and sub-section 1, clause (d) of the Industrial Disputes Act, 1947(in short the Act) for adjudication of an industrial dispute terms of which are as under:-

"Whether the action of the management M/s Central Institute of Plastics Engineering & Technology, Sonipat and M/s Super Detective Security Services Panipat in not accepting the demands regarding payment of final demands of the workmen Sh. Rakesh S/o Pala Ram, is legal and justified? If not, what relief the workman is entitled to and from which date?"

It is clear from the statement of claim that workman was appointed with respondent no.1 i.e. M/s Central Institute of Plastics Engineering & Technology, DCRUST Campus, 50th Mile Stone, NH-1, Murthal, Distt. Sonapat(Haryana),

which is a Central Government undertaking by following the due procedure under the Law. The workman has claimed arrears of the facilities like wages at double rates for working on Saturday and Sunday or any other holiday. Uniform and Safety Shoes, Dust Allowance, Annual Bonus, Annual Leave with wages after completion of 240 days.

The above facilities and allowances were not paid to the workman despite demand notice as such, claim was filed. No written statement was filed on behalf of the management. This Court tried conciliation between the parties and parties finally amicably settled the matter vide a settlement Exb.C-1. Statement of the workman has been recorded, who is accepted the settlement Exb.C-1. The workman does not want to pursue the claim petition.

Resultantly, the claim filed by the workman is settled in terms of Exb.C-1, which shall form integral part of this award.

Let copy of this award be sent to the Central Government for publication as required under Section 17 of the Act.

A. C. DOGRA, Presiding Officer-cum-Link Officer

नई दिल्ली, 2 जुलाई, 2018

का.आ. 1054.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार मैसर्स सेन्ट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक्स इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नोलॉजी एवं अन्य के प्रबंधन के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण एवं श्रम न्यायालय-1, चंडीगढ़ के पंचाट (संदर्भ संख्या 52/2015) को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 28.06.2018 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल-30012/18/2016-आईआर (एम)]

डी. के. हिमांशु, अवर सचिव

New Delhi, the 2nd July, 2018

S.O. 1054.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award (Ref. No. 52/2015) of the Central Government Industrial Tribunal/Labour Court-1, Chandigarh now as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of M/s. Central Institute of Plastics Engineering & Technology and other and their workman, which was received by the Central Government on 28.06.2018.

[No. L-30012/18/2016-IR (M)]

D. K. HIMANSHU, Under Secy.

ANNEXURE

BEFORE PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVT. INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT-I, CHANDIGARH

Case No. ID No. 52 of 2015

Sh. Raghubir Singh, S/o Sh. Jaswant Singh, Village & PO-Dadlana,
Tehsil & Distt. Panipat (Haryana)-132140

...Workman

Versus

1. M/s Central Institute of Plastics Engineering & Technology,
DCRUST Campus, 50th Mile Stone, NH-1, Murthal,
Distt. Sonapat (Haryana)-131027.

2. M/s Super Detective Security Services, Asandh Road,
Panipat (Haryana)-132103

...Respondents

Award Dated : 26.04.2018

A reference was received from the Government of India vide reference No.L-30012/18/2016-IR(M) Order Dated 14.03.2016 under Section 10 sub-Section 2(A) and sub-section 1, clause (d) of the Industrial Disputes Act, 1947(in short the Act) for adjudication of an industrial dispute terms of which are as under:-

“Whether the action of the management M/s Central Institute of Plastics Engineering & Technology, Sonipat and M/s Super Detective Security Services Panipat in not accepting the demands regarding payment of final demands of the workmen Sh. Raghubir Singh S/o Sh. Jaswant Singh, is legal and justified? If not, what relief the workman is entitled to and from which date?”

It is clear from the statement of claim that workman was appointed with respondent no.1 i.e. M/s Central Institute of Plastics Engineering & Technology, DCRUST Campus, 50th Mile Stone, NH-1, Murthal, Distt. Sonapat(Haryana), which is a Central Government undertaking by following the due procedure under the Law. The workman has claimed arrears of the facilities like wages at double rates for working on Saturday and Sunday or any other holiday. Uniform and Safety Shoes, Dust Allowance, Annual Bonus, Annual Leave with wages after completion of 240 days.

The above facilities and allowances were not paid to the workman despite demand notice as such, claim was filed. No written statement was filed on behalf of the management. This Court tried conciliation between the parties and parties finally amicably settled the matter vide a settlement Exb.C-1. Statement of the workman has been recorded, who is accepted the settlement Exb.C-1. The workman does not want to pursue the claim petition.

Resultantly, the claim filed by the workman is settled in terms of Exb.C-1, which shall form integral part of this award.

Let copy of this award be sent to the Central Government for publication as required under Section 17 of the Act.

A. C. DOGRA, Presiding Officer-cum-Link Officer